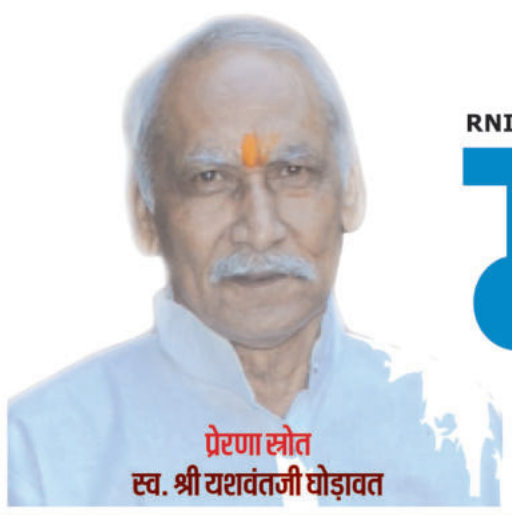

RNI No. MPHIN/2018/76422

माही की गूंज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-08, अंक - 31 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरूवार 21 मई 2026 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

सुविचार

जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते है

बीके शिवानी दीदी

वाह रे... सिस्टम जिंदा को मृत बताया...

खुद को जिंदा साबित करने में छुटा पसीना...

माही की गूंज, झाबुआ डेस्क।

संजय भटेवरा

कहने को मध्यप्रदेश में भाजपा की सुशासन वाली तथा डबल इंजन की सरकार है और यहां के मुख्यमंत्री हर बात के लिए आम जनता से दोनों हाथ उठवाकर जोरदार अभिनंदन कराते हैं...। लेकिन उन्ही के राज में जिंदा व्यक्ति को अपने जिंदा होने का सबूत पेश करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वह भी एक जनप्रतिनिधि को। सरकारी अस्पतालों में बच्चों को चूहे कुतर रहे हैं, डॉक्टर खुद जहरीला कफ सिरफ मरीजों को पिला रहे हैं। घर-घर नल से पानी पहुंचाने की योजना को वर्तमान में पानी के लिए मशक्कत करते लोगो की तस्वीरे चिढ़ा रही है। लाखों बच्चों के भविष्य का निर्धारण करने वाली परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। नेता जमीन की हेरा-फेरी करने में व्यस्त है। अधिकारी शौचालयों के निर्माण तक में रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार हो रहे हैं। कुल मिलाकर देश में अजीबो गरीब वाकिये ही चल रहे हैं। ऐसे में आम जनता के मन में एक ही सवाल है क्या यही भाजपा का सुशासन है...?

पंच रइसा बाई जिवित होने के बाद भी जिवित होने के प्रमाण के लिए ही भटक रही है।

क्या है मामला

हाल ही में रतलाम जिले की ग्राम पंचायत धतुरिया का है जहां एक महिला पंच रइसा बाई का आरोप है कि, उसने ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठाया। तो उसे पंचायत रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उसका मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया। जिसके बाद वे पिछले चार महीनो से खुद को जीवित साबित करने का प्रयास कर रही है लेकिन उसे अभी तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में सरकारी कार्यालयों में होने वाले कार्यों का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है जब जिंदा व्यक्ति को मृत बताया जा सकता है तो अन्य कार्यों की स्थिति क्या होगी। बतादे ऐसा मध्यप्रदेश में पहला मामला नही है इसके पहले भी थांदला पुलिस का एक मामला सामने आया था जिसमे भानपुरा (मंदसौर) थाना क्षेत्र की जिवित महिला की हत्या होना बता कर बैगुनाहो को जेल की हवा खिला चुके है।

नीट पेपर लीक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़

पिछले कुछ वर्षों से भर्ती परीक्षाओं में धांधली के आरोप सरकार पर लगते रहे हैं। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले के बाद कई मामले सामने आ चुके हैं बावजूद इसके ये कम होने के बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में पेपर लीक होने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया और पुनः परीक्षा की तारीख घोषित की गई। जिससे लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो गए है। परीक्षा भले ही दुबारा हो जाएगी लेकिन लाखों छात्रों ने इस दौरान जो तनाव झेला उसका क्या...? लाखों छात्र अपने भविष्य की चिंता को लेकर महगे कोचिंग संस्थानों में प्रवेश लेते हैं तो केवल छात्र ही नहीं बल्कि उसके पालकों की उम्मीद और सपने भी जुड़े होते हैं। ऐसे में पेपर लीक होने के बाद एक बार पुनः सरकार की नाकामियों की कीमत उन्हें दोबारा परीक्षा देकर चुकानी पड़ेगी। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मीम्स चल रहे हैं कुछ लोग लिख रहे हैं कि 10 रुपए का बच्चों का डायपर लीक नहीं होता है। ऐसे में इतनी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक कैसे हो गया...? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि, सरकार देश के युवाओं को स्वस्थ्य प्रतियोगिता उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। हर जगह माफियाओं का राज हो गया है, भू-माफिया के बाद शिक्षा माफिया सक्रिय हो गए हैं। जो कहने को कोचिंग सेंटर चलाते हैं लेकिन असल में वे शिक्षा का व्यापार कर रहे हैं जो लाखों रुपए लेकर बच्चों को पहले ही पेपर दिलवा देते हैं। ऐसे में साल भर ईमानदारी से मेहनत करने वाले छात्रों को निराशा हाथ लगती है। कई लोगों का कहना है कि, नकली खाद बीज तो किसान का एक वर्ष बर्बाद करता है लेकिन इस तरह के पेपर का लिक होना लाखो छात्रों का भविष्य ही बर्बाद कर देता हैं। ऐसे में इस प्रकार की घटनाओं पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होना चाहिए। वही दोशियों को कठोरतम दंड देना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो पाए।

देश आर्थिक संकट की और महंगाई बढ़ने की आशंका - राहुल गांधी

रायबरेली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रायबरेली के लोधवारी गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरा पासी की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के दौरान आयोजित बहुजन स्वाभिमान सभा में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश आने वाले समय में आर्थिक संकट की ओर बढ़ सकता है और इसका सबसे अधिक असर आम जनता पर पड़ेगा।

राहुल गांधी ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच टकराव के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित हो रहा है। उनका कहना था कि होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावित होने से तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो सकती है, जिससे देश में महंगाई बढ़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल, रसोई गैस और दैनिक उपयोग की वस्तुएं आने वाले समय में और महंगी हो सकती हैं।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आम लोगों की समस्याओं से दूर होती जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यदि आर्थिक हालात बिगड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कठिनाइयों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा।

सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने संविधान और सामाजिक समानता के मुद्दे पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि वीरा पासी और भीमराव आंबेडकर ने समाज में समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि देश में हर नागरिक समान है और सभी को अपने परिश्रम का पूरा अधिकार मिलना चाहिए।

राहुल गांधी ने कहा कि भारत किसी एक जाति या संगठन का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों का देश है। उन्होंने कहा कि संविधान देश की जनता की आवाज है और उसकी रक्षा करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सभा के दौरान उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि केवल नारों से बदलाव नहीं आएगा, बल्कि संविधान की रक्षा से ही अधिकार सुरक्षित रहेंगे।

उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी संविधान की मूल भावना को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना समय की आवश्यकता है।

ऑनलाइन दवा बिक्री: विरोध में देशभर के केमिस्टों की हड़ताल

नई दिल्ली।

ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री के विरोध में बुधवार को देशभर के केमिस्टों और दवा व्यापारियों ने देशव्यापी हड़ताल की। दवा विक्रेताओं के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन के चलते देशभर में करीब 12 लाख से अधिक निजी मेडिकल स्टोर बंद रहे। हड़ताल के कारण कई स्थानों पर मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

दवा व्यापारियों का आरोप है कि कई ई-फार्मेसी और डिजिटल मंच बिना पर्याप्त नियामकीय निगरानी के दवाओं की बिक्री कर रहे हैं। उनका कहना है कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर चिकित्सकीय पर्चों की सही तरीके से जांच नहीं की जाती और दवाओं के सुरक्षित भंडारण तथा वितरण से जुड़े नियमों का भी पूरी तरह पालन नहीं हो रहा है।

केमिस्ट संगठनों ने चेतावनी दी कि ऑनलाइन माध्यम से अनियंत्रित दवा बिक्री के कारण नकली दवाओं का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रतिबंधित और डॉक्टर की सलाह पर मिलने वाली दवाइयों का गलत उपयोग भी तेजी से बढ़ सकता है। दवा व्यापारियों ने विशेष रूप से नशीली और अनुसूची एच श्रेणी की संवेदनशील दवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बिना उचित जांच के ऐसी दवाओं की बिक्री युवाओं में नशे और दवाओं के दुरुपयोग को बढ़ावा दे सकती है।

दवा विक्रेताओं ने कहा कि, पारंपरिक मेडिकल स्टोर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत तय नियमों का पालन करते हैं। इसमें चिकित्सकीय पर्चे की जांच, दवा की मात्रा सीमित रखना और रिकॉर्ड संधारित करना अनिवार्य होता है। जबकि कई ऑनलाइन मंचों पर ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाओं की कमी देखी जा रही है।

संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार की दवा दुकानों पर समान नियम लागू किए जाने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कई जीवनरक्षक दवाओं को निर्धारित तापमान में सुरक्षित रखना आवश्यक होता है, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी के दौरान तापमान नियंत्रण में लापरवाही बरती जाती है, जिससे दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। दवा व्यापारियों ने सरकार से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण और स्पष्ट नियम लागू करने की मांग की है।

मेटा में बड़े स्तर पर कर्मचारियों की छंटनी, एआई आधारित पुनर्गठन शुरू

नई दिल्ली, एजेंसी।

सोशल मीडिया कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स ने संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव करते हुए करीब 8 हजार कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। यह कदम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तकनीक के बढ़ते उपयोग और कंपनी के पुनर्गठन की योजना के तहत उठाया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को छंटनी संबंधी सूचनाएं भेजना शुरू कर दिया है।

रिपोर्टों में दावा किया गया है कि इस पुनर्गठन से वैश्विक स्तर पर कंपनी के करीब 10 प्रतिशत कर्मचारी प्रभावित हो सकते हैं। वहीं हजारों कर्मचारियों की भूमिकाओं में भी बदलाव किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि मेटा करीब 7 हजार कर्मचारियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नई जिम्मेदारियों में स्थानांतरित करने की तैयारी कर रही है। कंपनी की मानव संसाधन प्रमुख जेनेल गेल द्वारा कर्मचारियों को भेजे गए एक आंतरिक संदेश में कहा गया है कि कई टीमों का पुनर्गठन कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सिद्धांतों के अनुसार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छोटी और सरल कार्य संरचनाएं तैयार करना है, जिससे कर्मचारी अधिक जिम्मेदारी के साथ तेजी से काम कर सकें।

मेमो में यह भी उल्लेख किया गया कि नई संगठनात्मक संरचना तैयार करते समय कई टीमों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजाइन सिद्धांतों को अपनाया है। कंपनी का मानना है कि इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी और भविष्य की तकनीकी जरूरतों के अनुसार संगठन को मजबूत बनाया जा सकेगा।

रिपोर्टों के अनुसार उत्तरी अमेरिका में कर्मचारियों को छंटनी प्रभावी होने वाले दिन घर से काम करने के निर्देश दिए गए थे। मेटा इससे पहले भी छंटनी के दौरान इसी प्रकार की प्रक्रिया अपना चुकी है। यह पुनर्गठन ऐसे समय में किया जा रहा है जब मेटा कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है। कंपनी ने वर्ष 2026 के लिए 125 अरब डॉलर से 145 अरब डॉलर तक पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाया है। यह निवेश मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता डेटा केंद्रों, विशेष चिप निर्माण और मॉडल प्रशिक्षण पर किया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कंपनी द्वारा एकत्रित किए जा रहे आंकड़ों का उद्देश्य केवल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालियों को बेहतर बनाना है, न कि कर्मचारियों की निगरानी करना।

हिंद महासागर तक बढ़ा अमेरिका-ईरान तनाव, तेल टैंकर जब्त होने से बढ़ी हलचल

नई दिल्ली।

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब होर्मुज जलडमरूमध्य से आगे हिंद महासागर तक पहुंच गया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अमेरिका ने हिंद महासागर क्षेत्र में ईरान से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त किया है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बढ़ा रहे हैं और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं।

जब्त किए गए जहाज की पहचान स्काईवेव के रूप में हुई है। अमेरिकी प्रशासन का आरोप है कि यह टैंकर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी कच्चे तेल की ढुलाई कर रहा था। इसी कारण मार्च में इस जहाज पर प्रतिबंध लगाए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक यह जहाज ईरान के तथाकथित छाया बेड़े का हिस्सा था। इस नेटवर्क का उपयोग अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचते हुए तेल निर्यात के लिए किया जाता है।

जहाजों की निगरानी से जुड़े आंकड़ों के अनुसार यह टैंकर मंगलवार को मलेशिया के पश्चिमी समुद्री क्षेत्र से गुजरते हुए मलक्का जलडमरूमध्य पार कर चुका था। समुद्री व्यापार से जुड़े सूत्रों और लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार जहाज में 10 लाख बैरल से

अधिक कच्चा तेल मौजूद हो सकता है। बताया जा रहा है कि यह तेल फरवरी में ईरान के खार्ग द्वीप से लादा गया था, जिसे ईरान का प्रमुख तेल निर्यात केंद्र माना जाता है।

अमेरिका इससे पहले भी ईरान से जुड़े तेल जहाजों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। अप्रैल में अमेरिकी प्रशासन ने हिंद महासागर क्षेत्र में मेजेस्टिक एक्स और टिफानी नामक दो अन्य जहाजों को भी जब्त किया था। अमेरिका का दावा था कि ये जहाज भी प्रतिबंधों का उल्लंघन कर ईरानी तेल की ढुलाई कर रहे थे।

दरअसल अमेरिका लंबे समय से ईरान के तेल कारोबार और परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन का आरोप है कि तेल निर्यात से होने वाली आय का उपयोग ईरान अपनी मिसाइल क्षमता बढ़ाने और क्षेत्रीय सहयोगी समूहों को मजबूत करने में करता है। इसी कारण ट्रंप प्रशासन आर्थिक प्रतिबंधों और समुद्री निगरानी को लगातार सख्त बना रहा है।

इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह ईरान पर नए सैन्य हमले का फैसला लेने से सिर्फ एक घंटे दूर थे, लेकिन खाड़ी देशों के आग्रह पर निर्णय टाल दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर अमेरिकी शर्तें नहीं मानीं, तो आगे और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि हिंद महासागर और अरब सागर क्षेत्र में बढ़ती यह तनातनी वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दुनिया के प्रमुख तेल मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं।

रोम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, जॉर्जिया मेलोनी ने कहा- स्वागत है मेरे दोस्त

रोम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंच गए। यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मेलोनी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर संदेश जारी करते हुए लिखा, रोम में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस आधिकारिक यात्रा के दौरान भारत और इटली के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई अहम समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यह यात्रा भारत और इटली के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के उद्देश्य से है।बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच ऐतिहासिक विला डोरिया पाम्फिली में महत्वपूर्ण बैठक होगी। राजनयिक सूत्रों के अनुसार बैठक के बाद दोनों देश संयुक्त घोषणा पत्र जारी कर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि इटली के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने स्वयं हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत और इटली के संबंधों को नई गति प्रदान करेगी। दोनों देश वर्ष 2025 से 2029 तक की संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। हाल के वर्षों में भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। वर्ष 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16.77 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो बढ़ते आर्थिक सहयोग का संकेत है।

खुलासा: महंगे शौक तथा ऐशो-आराम की पूर्ति के लिए मौसी के घर में घुसकर किया प्राणघातक हमला व की लूट

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद थाना क्षेत्र में 5 मई को ग्राम कोदली में हुई 6 वर्षीय मासुम बालक उत्कर्ष की निर्मम हत्या ओर लुट की वारदात के बाद से पुलिस पर इस मामले को ट्रेस करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। लगातार छानबीन ओर साक्ष्यो को जोड़कर मामले के आरोपियों तक पहुंचने के पुलिस के प्रयासों को आखिर सफलता मिली। घटना के बाद से शक किसी अपने ओर मिलने जुलने वाले की ओर जा रहा था ओर इसी दिशा में पुलिस की खोजबीन जारी थी। अब जाकर पुलिस को सफलता मिली ओर वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने पकड़ कर पूरी वारदात से पर्दा उठाया। वारदात को अंजाम देने वाले पीड़ित परिवार के रिश्तेदार ही थे।

ये था पूरा घटनाक्रम

5 मई को ग्राम कोदली निवासी मृतक उत्कर्ष पिता शैलेन्द्र नायक उम्र 6 वर्ष एवं घायल रमीलाबाई पति कुशलसिंह नायक उम्र 53 वर्ष अपने घर की छत पर गंभीर घायल अवस्था में खून से लथपथ मिले। परिजनों द्वारा दोनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पेटलावद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मासूम उत्कर्ष को मृत घोषित कर दिया। 6 मई 2026 को हुए पोस्टमार्टम में डॉक्टरों द्वारा बालक की मृत्यु मानव द्वारा कारित चोटों से होना बताया गया। इसके आधार पर थाना पेटलावद में अपराध क्रमांक 226/2026 धारा 103(1), 109(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ देवेन्द्र पाटीदार द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया, एसडीओपी पेटलावद अनुरक्ति साबनानी एवं थाना निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया को आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। तकनीकी साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों ने उक्त घटना को करना स्वीकार किया।

दोनों आरोपी धराए

वारदात में शामिल दोनों आरोपी जितेन्द्र उर्फ जितु पिता स्व. शंकर नायक उम्र 24 वर्ष निवासी छायन थाना राणापुर, हाल सिद्धेश्वर कॉलोनी झाबुआ ओर चिराग पिता राजेश नायक उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम कोदली है। जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने स्वीकार किया कि, वे अपने महंगे शौक एवं ऐशो-आराम की पूर्ति के लिए पैसों की तलाश में थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने रमीलाबाई को घर में अकेला पाकर उन पर हमला किया तथा उनके पोते उत्कर्ष की फावड़े से वार कर हत्या कर दी। आरोपियों ने रमीलाबाई के कानों से सोने के टॉप्स छीन लिए एवं घर में रखी सोने की अंगूठी एवं चांदी की चेन लूटकर फरार हो गए। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया।

मृतक उत्कर्ष नायक।

पुलिस ने आरोपियो को किया गिरफ्तार।

सराहनीय कार्य

मासूम बालक उत्कर्ष की हत्या एवं रमीलाबाई पर प्राणघातक हमला करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं घटना के सफल खुलासे में थाना प्रभारी निरीक्षक निर्भयसिंह भूरिया, उप निरीक्षक गोवर्धन मकवाना, उप निरीक्षक अर्चना चौहान, सउनि लाखनसिंह भाटी, प्रधान आरक्षक 255 अरविन्द बारिया, प्रधान आरक्षक 380 मनोज भूरिया, आरक्षक 527 अनिल अमलियार, आरक्षक 303 विकास यादव, आरक्षक 282 राकेश डामर, आरक्षक 227 महेन्द्र चन्देल, आरक्षक 259 राजेन्द्र परिहार, आरक्षक 343 घनश्याम मालवीय, आरक्षक 164 वेरसिंह कलेश, चालक आरक्षक 623 मोतीलाल डिण्डोर एवं साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई।

अभिभावकों से अपील

झाबुआ पुलिस सभी अभिभावकों से अपील करती है कि वे अपने बच्चों एवं युवाओं की गतिविधियों, मित्र मंडली एवं खर्च करने की आदतों पर नियमित निगरानी रखें। कई बार महंगे शौक, दिखावे की प्रवृत्ति एवं गलत संगति युवा पीढ़ी को अपराध की ओर धकेल देती है। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पारिवारिक संस्कार एवं सही मार्गदर्शन देना समाज और परिवार दोनों की जिम्मेदारी है।

संदिग्ध हालत में युवक का मिला शव, हत्या की आशंका

माही की गूंज ,करवड़। अरुण पाटीदार

पेटलावद थाना क्षेत्र के करवड़ पुलिस चौकी के अंतर्गत मंगलवार को जीवरी नाका मोर के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान शांतिलाल पारगी पिता वेलजी पारगी, निवासी चंवरापाड़ा मोर पंचायत के रूप में हुई थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शांतिलाल जवरी खाली नाका मोर में मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। मृतक के चेहरे पर चोट के गहरे निशान पाए गए हैं। जिससे मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। घटना की भनक लगते ही आस-पास के इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना करवड़ पुलिस को दी। सूचना मिलते ही करवड़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकता है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार ने भी घटना स्थल पर पहुंच कर मौके का जायजा लिया और जल्द ही हत्या के खुलासे के निर्देश पेटलावद पुलिस को दिए। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हत्या को अंजाम देने वाले आरोपी की पहचान हो चुकी है एवं अवैध संबंधों को लेकर हत्या होने के कयास लगाए जा रहे है। मामले में पुलिस के खुलासे के बाद ही पूरा घटनाक्रम सामने आयेगा।

सप्त दिवसीय भागवत कथा का शुभारम्भ आज से....

माही की गूंज, भामल।

ग्राम भामल में श्री सत्यवीर तेजाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा की 9 वी वर्षगांठ पर संगीतमय श्रीमद भागवत कथा एवं एक कुण्डीय यज्ञ का आज शुभारम्भ हो कर 28 मई तक कथा का आयोजन होगा। जिसमे मुख्य अतिथि के रूप मे पिपलखुटा (मेघनगर) 1008 महर्षि दयानद महाराज की उपस्थिति के साथ कथा वाचक पं. पवनजी शर्मा एवं यज्ञ आचार्य प. लखनजी शर्मा के सानिध्य से सप्त दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ किया जाएगा। जिसमे आज प्रथम दिन कथा की शुरुआत कलशयात्रा के साथ शाम साढ़े 4 बजे से शुरू की जाएगी। एवं महायज्ञ प्रारम्भ 24 मई रविवार को प्रातः 9 बजे से शुरू होगा। पूर्णाहुति 28 मई को की जाएगी कथा सुनने का समय रात्री 8 से 11 बजे तक रहेगा। कथा स्थान सत्यवीर तेजाजी महाराज बेडावा रोड भामल मे की जाएगी। आयोजक समिति के सदस्य नारायण पालरा, दिनेश पालरा रूघनाथ राठौर आदि ने जानकरी देते हुए बताया कि, सात दिवसीय कथा की शुरूआत बड़ी धूम धाम से की जाएगी। जिसमे समस्त धर्म प्रेमी जनता सःपरिवार सादर आंमत्रित है। आयोजन समस्त ग्रामवासी एवं राजपुत समाज द्वारा किया जा रहा है। कथा के अंतिम दिन शोभायात्रा एवं महाप्रसादीं का आयोजन होगा।

श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर हो रही शिव पुराण कथा

माही की गूंज, काकनवानी। नरेश पंचाल

शिव कैलाशो के वासी धोरी धार के वासी, शंकर संकट हरना ओ मोरे बाबा शंकर संकट हरना, के भजन से शुरुआत कर बताया कि, कथा वही है जो हमारे जीवन को बदल दे, जीना उसी का धन्य है जो जीवन के लिए जानता हो। मनुष्य और जानवर सब एक समान होते है खाना, पीना, सोना, बैठना, उठाना सारी चीज एक ही समान होती है। मानव जीवन हमें परमात्मा ने दिया है जो की यह मानव जीवन 84 लाख योनि में आता है हम अभी 83 लाख यानी जी चुके हैं और अब हम 84 लाख योनि में हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें इस मनुष्य योनि में नेक काम करना चाहिए पूजन पाठ भगवान का नाम और जितना हो सके लोगों का सहयोग करना चाहिए। मानव जीवन हमें परमात्मा ने दिया है कई जगह कथाएं होती है जहां पर इस मनुष्य योनि में हमें जगाने का काम करते हैं जो आदमी सोया है उसे जगाना तो आसान है लेकिन जो सोने का नाटक करता है उसे जगाना मुश्किल होता है।

महाराज जी ने कथा में बताया कि, जीना उसी को माना जाता है जो जीवन जीना जानता है जो ब्राह्मण होकर भी सत्कर्म नहीं करता, पूजा पाठ नहीं करता ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है। हर घर के आंगन में तुलसी होना चाहिए जिस घर के आंगन में तुलसी नहीं हो उस घर का पानी भी पीना उचित नहीं है। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है जो रोजाना स्नान, ध्यान करके तुलसी पूजा कर भगवान को तुलसी का एक पत्ता भी चढ़ाता है तो वह स्वर्ण के समान माना जाता है।

हमारा शास्त्र कहता है कि अतिथि देवो भव हमें हमारे द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत सत्कार कर उन्हें भोजन आदि करवाना चाहिए। अगर कोई भिक्षु भी हमारे द्वार पर आता है तो उसे भी खाने पीने का सामान देना चाहिए।

हमारे सनातन हिंदू धर्म में गाय को माता मानते हैं इसलिए हमें गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौ माता के शरीर में सभी देवी देवताओं का वास होता है गौ माता हमारे लिए पूज्यनी है। इसके पश्चात एक भजन के माध्यम से गुरु जी ने समझाया कि हमारे जीवन को सुधारना चाहिए हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए सभी नशे से दूर रहना चाहिए।

शिव पुराण कथा रोजाना दोपहर 1 से 4 बजे तक की जा रही है। इस कथा के कथावाचक पंडित श्री शैलेंद्र जी शास्त्री शिव कोठी ओमकारेश्वर हैं एवं कथा के संयोजक श्री श्री 108 श्री रामदास जी त्यागी जिन्हे इस क्षेत्र में टाट वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। यह कथा 19 मई से शुरू होकर 25 मई 2026 तक चलेगी। प्रतिदिन रात्रि में भजन संध्या के साथ रामायण मंडल ग्रुप एवं श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर समिति के पदाधिकारी एवं सदस्यों का भरपूर सहयोग हो रहा है।

जल जीवन जल मिशन मे बनी टंकी मे पानी ही नही पहुंचा

माही की गूंज, खवासा। सुनिल सोलंकी

मामला: थांदला जनपद की ग्राम पंचायत तलावड़ा का

गर्मी में अधिक तापमान बढ़ने के साथ ही ग्रामीण अंचलों में पानी की समस्या भी विकराल रूप लेने को उतारू हो गई है। ग्रामीण अंचलों में बनी जल जीवन जल मिशन के अंतर्गत पानी की टंकियां तो बना दी गई। लेकिन धरातल पर ग्रामीणों को नलों से पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। जब इतनी बड़ी पानी की टंकी बनाने के बाद अगर गांव में पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो आखिर किस तरह से सरकार का पैसा बर्बाद हुआ यह सहज ही अंदाज लगाया जा सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बाद भी अगर धरातल पर पानी ग्रामीणों को नही मिल पा रहा है। तो आखिर इसे आप क्या समझेंगे। कहीं ना कहीं लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग झाबुआ अधिकारियों के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है।

ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार थांदला जनपद क्षेत्र अंतर्गत खवासा कलस्टर की ग्राम पंचायत तलावड़ा में केसरपुरा, सादैड़ा व गड़ीफलिया में तीन जगह पानी की टंकियां का निर्माण किया गया है। निर्माण एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग झाबुआ है। तथा ठेका प्रगति कंस्ट्रक्शन कंपनी नई दिल्ली को मिला हुआ था। कार्य काफी कछुआ गति से किया गया तथा आज भी कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। कई जगह नली लगाकर ऐसे ही नल छोड़ दिए गए। तो वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि, एक बार पानी टेस्टिंग करने के बाद दूसरी बार नलों में पानी ही नहीं आया। वही ग्राम पंचायत की ओर से तर्क दिया गया कि, अभी तक कोई भी टंकी हैंडओवर नहीं की गई है। यानी अधूरा कार्य अभी भी बना हुआ है। बताते हैं कि, केसरपुरा व सादेड़ा में समवेल टंकी बनाई गई है, वही गड़ी फलिया मे एक बड़ी टंकी बनाई गई। वही केसरपुरा फलिया माही नदी के अंतिम छोर पर वहां पानी पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन फिर भी वहां नलों में ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो रहा है। वही सादेड़ा में तो समवेल टंकी बना दी गई। लेकिन कुआं खोदा ही नहीं गया ग्रामीणों को वहां भी पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि, कई घरों में तो नल तक नहीं लगाए गए। इतनी भीषण गर्मी के बाद भी ग्राम पंचायत व पीएचई विभाग द्वारा इस और कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। जिससे ग्रामीणों को पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ रहा है। तो वही गांव के कुछ युवाओं ने सोशल मीडिया पर भी जल जीवन जल मिशन पानी की टंकियों को लेकर काफी बहस छिड़ी हुई है। वही ग्रामीण सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया पानी को लेकर दे रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि, जब योजना सुचारू रूप से यहां शुरू की गई तो हमें लगा था कि और पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन यहां तो अब भी पहले जैसी स्थिति बनी हुई है। टंकी बना दी गई लेकिन नलों में पानी आया ही नही है।

मामले में एसडीओ पीएचई राहुल सोलंकी थांदला ने बताया कि, केसरपुरा में तो टंकी हेंडओवर कर दी गई है। सादेड़ा में कुएं का कार्य बाकी है, जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। और जहां भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा।

आकाश कार्यकारिणी का हुआ गठन

माही की गूंज, पेटलावद।

स्थानीय डाक बंगला परिसर में आदिवासी कर्मचारी अधिकारी की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ब्लॉक के कर्मचारी व अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक में कर्मचारियों के हितों व संरक्षण के लिए आदिवासी कर्मचारी-अधिकारी संगठन एकेएएस का गठन प्रांतीय महासचिव मगनसिंह बघेल ,प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य जीएल मंडलोई, के निर्देशन में आकाश जिलाध्यक्ष नानूराम गामड़ एवं उपाध्यक्ष कमलेश ताड़ ने सर्व सहमति से ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया। जिसमें संरक्षक प्रवीण कुमार डामर, अध्यक्ष तोलसिंह निनामा, कार्यकारी अध्यक्ष रामलाल कटारा सहित अन्य कर्मचारियों को पदभार दिया गया।

घायल व्यक्ति की जान बचाने वाले को मिला राहवीर सम्मान

माही की गूंज, झाबुआ।

परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश कार्यालय, ग्वालियर द्वारा झाबुआ निवासी भावेश पिता विनोद सोलंकी को सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता कर उसकी जान बचाने के लिए प्रशस्ति पत्र कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने भेंट किया।

भावेश सोलंकी ने 19 अगस्त 2025 को हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पीड़ित को गोल्डन ऑवर के दौरान तत्काल निकटतम अस्पताल ट्रॉमा सेंटर पहुंचाकर मानवता एवं संवेदनशीलता का परिचय दिया गया। उनकी तत्परता एवं सजगता से घायल व्यक्ति को समय पर उपचार मिल सका और उसकी जान बचाई जा सकी।

परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा श्री सोलंकी के इस सराहनीय एवं प्रेरणादायी कार्य की प्रशंसा करते हुए उन्हें ÷राह-वीर÷ के रूप में सम्मानित किया गया।

उम्मीदों की जनसुनवाई : नवागत कलेक्टर के प्रयासों को लगे पंख, रिकार्ड तोड़ 166 आवेदन आए

विकास खंड स्तर पर होने वाली जनसुनवाई धराशाई, अधिकारियों की बेरूखी बनी वजह

सरकार के दावे फेल, लोगों की परेशानी का नही हो पा रहा हल, शिकायत बंद करवाने में लगे रहते है अधिकारी

आवश्यक दिशा निर्देश, शांति से सुनी समस्या

माही की गूंज, पेटलावद। राकेश गेहलोत

मंगलवार को नवागत कलेक्टर योगेश तुकाराम भरसट के नेतृत्व में जनपद पंचायत कार्यालय पेटलावद में सम्पन्न हुई जनसुनवाई कार्यक्रम उम्मीदों की जन सुनवाई बन कर उभरी है। नए कलेक्टर के आने के बाद ही झाबुआ मुख्यालय पर आयोजित होने वाली जन सुनवाई में सैकड़ों की भीड़ देख कर कलेक्टर खुद अचंभित दिखे। लोग अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए 50 से 80 किलोमीटर दूर से भरी गर्मी में झाबुआ पहुंच रहे है जिसमें जिले के सभी विकास खंडों से लोग जाते है। हालांकि हर मंगलवार को विकास खंड स्तर पर भी जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित होते है लेकिन लोगों को स्थानीय अधिकारियों से न्याय नहीं मिल पाता जिससे लोग उम्मीद लेकर कलेक्टर के पास पहुंच जाते है। जिला मुख्यालय पर आने वाली भीड़ को देखते हुए कलेक्टर योगेश तुकाराम ने विकास खंड स्तर पर पहुंच कर लोगों की समस्या सुनने का निर्णय लिया ओर शुरुवात पेटलावद विकासखंड से हुई।

पेटलावद जनसुनवाई में उमड़ी भीड़ ने एक बार फिर बता दिया की जनता न्याय ओर निराकरण के लिए जिला कलेक्टर पर ही भरोसा दिखा रही है। जिस जनसुनवाई में बमुश्किल दस से पंद्रह आवेदन आते है वहां कलेक्टर की उपस्थिति में 166 आवेदन आए। आलम ये था कि, जनसुनवाई स्थल जनपद कार्यालय में पैर रखने तक की जगह नहीं थी।

कितनी शिकायतों का निराकरण होगा और स्थानीय अधिकारी किस प्रकार की कार्रवाई करते है ये देखना दिलचस्प जरूर होगा। लेकिन इससे पहले कलेक्टर योगेश तुकाराम ने जनसुनवाई में आए लोगों की समस्याओं को शांति से सुना ओर निराकरण के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मीडिया से चर्चा में भी उन्होंने ये बात मानी कि, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना कही न कही चिंता का विषय है कि आखिर क्यों समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा। वही कलेक्टर ने कहा, पूरा प्रयास रहेंगा की ज्यादा से ज्यादा लोगों का निराकरण हो जाए और उन्हें भटकना नहीं पड़े। शिकायत की बात करे तो भले शिकायत कलेक्टर के पास पहुंची हो लेकिन घूम फिर कर मामला स्थानीय अधिकारी ओर स्थानीय विभाग में पहुंच जाता है जहां कलेक्टर साहब को भी स्थानीय अधिकारी हथेली में हाथी दिखाने में देर नहीं करेगें।

भूमि विवाद, बिजली बिल, जल संकट एवं शासकीय योजनाओं से जुड़े मामलों पर हुई सुनवाई

बामनिया के आवेदक ने मकान संबंधी मामले में आरोप लगाया कि, संबंधित भूमि सर्वे नंबर 104 नजूल की शासकीय भूमि है तथा ग्राम पंचायत द्वारा गलत आधार पर भवन प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन सचिव को टर्मिनेट करने के निर्देश दिए।

आवेदिका राधा पिता रामलाल पाल निवासी बामनिया ने विद्युत बिल में त्रुटि की शिकायत करते हुए बताया कि, बिल दिनांक 13 मई 2026 में मीटर रीडिंग 3233 दर्शा कर 551 यूनिट का बिल 5247 रुपए का जारी किया गया है। जबकि वास्तविक मीटर रीडिंग 2795 है तथा अप्रैल माह की रीडिंग 2682 होने से कुल 113 यूनिट ही बनती है। इस संबंध में आवेदन प्रस्तुत करने पर कलेक्टर ने एमपीईबी को जांच कर त्रुटि पाए जाने पर बिल में सुधार करने के निर्देश दिए।

आवेदिका रतन कुंवर पति स्व. मिठूसिंह राठौर निवासी डोगरे नगर रतलाम ने ग्राम घुघरी स्थित अपनी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत प्रस्तुत की। आवेदिका ने बताया कि, सीमांकन कराए जाने के बावजूद कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है, तथा विपक्षीगण वर्षों से भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। विधवा होने के कारण उन्हें न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

आवेदिका सुनीता पति सुभाष चन्द्र निवासी माधव कॉलोनी पेटलावद ने भू-राजस्व राशि जमा होने के बावजूद बकाया नोटिस एवं दोबारा वसूली किए जाने की शिकायत की। आवेदिका ने बताया कि, वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक की राशि ऑफलाइन जमा की गई थी, किन्तु अब उन रसीदों को अमान्य बताकर पुनः राशि जमा कराने का दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही पंचायत उपकर एवं भू-राजस्व की दोहरी वसूली का आरोप लगाया गया। मामले में संबंधित राजस्व अधिकारियों को जांच कर उचित निराकरण के निर्देश दिए गए।

आवेदक अंतोन कटारा, सहायक शिक्षक माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा ने तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान बंद किए जाने की शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि, 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर विभागीय क्रमोन्नति समिति की अनुशंसा से उन्हें तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत हुआ था, जो केवल दो माह प्राप्त होने के बाद जनवरी 2026 से बंद कर दिया गया। जबकि समान नियुक्ति तिथि वाले अन्य शिक्षकों को यह लाभ निरंतर दिया जा रहा है। कलेक्टर ने जनजातीय कार्य विभाग को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

आवेदक ईश्वरलाल पिता रतन पाटीदार निवासी ग्राम रामगढ़ पेटलावद ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत आवेदन लंबित होने की शिकायत की। आवेदक ने बताया कि, प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं पात्रता पूर्ण होने के बावजूद उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक के प्रबंधक को योजना अंतर्गत आवेदक को लाभान्वित करने के निर्देश दिए।

ग्राम मठमठ के ग्रामीणों ने नवीन पानी की टंकी में जल आपूर्ति प्रारंभ नहीं होने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि, वर्ष 2023-24 में निर्मित पानी की टंकी को माही नदी से पाइपलाईन द्वारा जोड़ने की योजना बनाई गई थी, किन्तु आज तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हुई। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं को दूर-दूर से पानी लाना पड़ रहा है। मामले में तत्काल जलापूर्ति शुरू कराने के निर्देश दिए गए।

आवेदक शम्भु पिता जवरा वाखला निवासी रायपुरिया ने फार्मर रजिस्ट्री में भूमि अपडेट नहीं होने की शिकायत प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि, फरवरी 2026 में ऑनलाइन आवेदन करने के बावजूद उनकी भूमि अब तक रजिस्ट्री में अपडेट नहीं हुई, जिसके कारण उन्हें कृषि हेतु खाद प्राप्त करने में समस्या आ रही है। संबंधित विभाग को शीघ्र आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

आवेदिका हकरी पति हरीराम मैडा निवासी ग्राम खाखरापाड़ा पंचायत गंगाखेड़ी ने ई-केवाईसी एवं बैंक खाते में धोखाधड़ी की शिकायत प्रस्तुत की। आवेदिका ने बताया कि, ग्राम पंचायत में नियुक्त मोबाईलाजर द्वारा उनके बैंक खाते से मोबाइल नंबर हटाकर अपना नंबर जोड़ दिया गया तथा फर्जी खाते के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि निकाली जा रही है। शिकायत करने पर झगड़ा एवं विवाद करने का आरोप भी लगाया गया। मामले में गंभीरता से जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। पेटलावद में आयोजित जनसुनवाई में कुल 166 आवेदन प्राप्त हुए। साथ ही ÷जन भागीदारी सबसे दूर, सबसे पहले÷ अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में 25 आभा आईडी, 17 आयुष्मान कार्ड, 6 आधार अपडेट तथा 1 नया आधार कार्ड बनाया गया।

आईएएस एसडीएम रही फैल, जनता से दूरी के चलते जन सुनवाई हुई फुस्स

कहने को तो पेटलावद में कलेक्टर रेंक की आईएएस अधिकारी तनुश्री मीणा एसडीएम के रूप में लगभग दो वर्षों से पदस्थ हैं लेकिन उनकी कार्यशैली ने विकास खंड की व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ कर रख दिया। उनका आम जनता से दूरी , शिकायती आवेदनों पर बेरुखी और स्थानीय अधिकारीयों के साथ सामंजस्य की कमी के चलते विकास खंड स्तर पर होने वाली जन सुनवाई पूरी तरह फ्लॉफ शो बन कर रह गई। ज्यादातर जनसुनवाई कार्यक्रम में खुद एसडीएम ही नदारत रही। गिने चुने आवेदनों के बीच स्थानीय अधिकारी जन सुनवाई में मोबाईल चलाते ही नजर आते रहे। किसी विभाग पर सख्त नहीं देखी गई ,आवेदन ,ज्ञापन ओर दूसरे विषयों पर मेडम, सरकार की किरकिरी करती रही है जिससे प्रशासन पर आम जनता का विश्वास खत्म होता दिखाई देने लगा।

सरकार के दावे फैल ,शिकायत बंद कराने में व्यस्त अधिकारी

सरकार ने आम जनता की शिकायतों के निराकरण के लिए जनसुनवाई के साथ-साथ सीएम हेल्पलाइन से शिकायत की व्यवस्था की है, जिस पर रोज शिकायते दर्ज होती है। सरकार अपनी इस व्यवस्था को आम जनता का हितैषी बताकर समय-समय पर वाहवाही लूटती है लेकिन हकीकत सरकार के दावों से बिल्कुल परे है। जनसुनवाई कार्यक्रम अपनी पहचान खो चुके हैं। वहीं सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की बजाए शिकायत बंद कैसे की जाए उस पर अधिकारी काम करते नजर आते है। कई बार तो शिकायत कर्ताओ पर कही न कही से दबाओ तक बना कर, तो कई बार जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर शिकायत बंद करवा दी जाती है। शिकायतों पर निराकरण जमीनी हकीकत से कोसो दूर होते है। नए कलेक्टर के प्रयास कितने सार्थक होते है और कितनी शिकायतों का निराकरण होने के बाद अगले मंगलवार को जन सुनवाई में क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा।

पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति पर आक्रोश,सड़कों पर उतरे मोबिलाइजर

विधायक ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा के खिलाफ नारेबाजी

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्य प्रदेश के झाबुआ और पेटलावद में पेसा मोबिलाइजरों की सेवा समाप्ति के विरोध में आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शासन द्वारा हाल ही में जारी किए गए आदेश के बाद से आहत इन मोबलाइजरों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन के दौरान पेटलावद में भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, वहीं झाबुआ में आयोजित प्रदर्शन में स्थानीय विधायक डॉ. विक्रांत भूरिया ने भी शिरकत की। डॉ. भूरिया ने सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि, इन युवाओं की नियुक्ति केवल चुनाव के समय राजनीतिक लाभ लेने के लिए की गई थी और अब काम निकल जाने के बाद इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से शासन के 8 मई 2026 के पत्र क्रमांक 8448 पं. राज, आरजीएसए -83, 2026 को चुनौती देते हुए इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की है। मोबिलाइजरों का कहना है कि, वे सभी झाबुआ के अत्यंत निर्धन परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और स्वयं भी पेसा अधिनियम के दायरे में आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले आठ महीनों से उन्हें मानदेय तक नहीं दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में पेसा कानून के प्रचार-प्रसार और जन-जागरूकता फैलाने का काम पूरी निष्ठा से किया। अब बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उन्हें अचानक सेवा से हटा दिया गया है, जिससे उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट पैदा हो गया है।

इस निर्णय से दुखी और आक्रोशित प्रदर्शनकारी ने सरकार की मंशा पर गहरा संदेह जताया है। उन्होंने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि, इस स्थिति ने उन्हें न घर का छोड़ा है और न घाट का। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि, इससे बेहतर तो यह होता की सरकार उन्हें और उनके परिवार को वल्लभ भवन बुलाकर वहीं सुसाइड करवा देती... ! क्योंकि इस दौरान सरकारी काम में व्यस्त रहने के कारण वे अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए और अब उम्र निकल जाने के कारण उन्हें कहीं और नौकरी भी मिलना मुश्किल है। सड़क पर आ चुके इन युवाओं का कहना है कि, सरकार के इस मनमाने फैसले ने उनके भविष्य को पूरी तरह अंधकारमय बना दिया है।

चोरी का खुलासा, साढ़े 5 लाख का शत-प्रतिशत मशरूका जप्त

माही की गूंज, रायपुरिया।

15-16 मई की दरमियानी रात को कस्बा झकनावदा की मुस्लिम बस्ती में रहने वाले फरियादी मेहमूद पिता शकूर खान एवं आसिफ पिता आजाद खान अपने परिवार के साथ उर्स मेला देखने सरदारपुर गए हुए थे। इसी दौरान सूने मकान का फायदा उठाकर अज्ञात बदमाशों ने छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। बदमाशों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर 2 लाख 22 हजार नगद एवं सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर लिए, जिनकी कुल कीमत लगभग साढ़े 5 लाख थी।

फरियादी की रिपोर्ट पर थाना रायपुरिया में अपराध क्रमांक 156/2026, धारा 305(क), 331(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

19 मई की रात्रि में मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी रिजवान पिता रमजान खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी झकनावदा, संग्राम पिता दरियावसिंह मखोड़, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम भुरीघाटी को गिरफ्तार किया।

आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने फरियादी के घर से चोरी गया शत-प्रतिशत मशरूका बरामद करने में सफलता प्राप्त की।

कार्यालय नगर परिषद, पेटलावद जिला-झाबुआ (म.प्र.)

दूरभाष/फैक्स नं. 07391-265439 Email - cmopetlawad@mpurban.gov.in

क्रमांक/26/959 पेटलावद, दिनांक 13/05/2026

:: प्रथम ई-निविदा सूचना::

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत पंजीयन प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों/सप्लायर्स से आनलाईन निविदाये प्रतिशत/आईटम दर पर आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाईट https://mptender.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं ईएमडी	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_506381	CONSTRUCTION OF R.C.C. NALI AND PAVER BLOCK WORK IN W.NO. 03 (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 1.63 लाख	1. 1000/- 2. 3000/-	
2	2026_UAD_506382	CONSTRUCTION OF R.C.C. NALI WORK IN W.NO. 05 UDAY GARDEN (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 1.40 लाख	1. 1000/- 2. 3000/-	
3	2026_UAD_506383	CONSTRUCTION OF R.C.C. WATER TANK WORK IN W.NO. 09 (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 2.17 लाख	1. 1500/- 2. 4500/-	
4	2026_UAD_506384	CONSTRUCTION OF R.C.C. NALI WORK FROM RATHOD HOUSE TO BARBETA HOUSE IN W.NO. 10 (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 6.83 लाख	1. 2000/- 2. 13500/-	
5	2026_UAD_506385	CONSTRUCTION WORK OF 02 FISH PARLOUR IN W.NO. 13 (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 8.47 लाख	1. 2000/- 2. 17000/-	
6	2026_UAD_506386	CONSTRUCTION OF R.C.C. NALI WORK FROM GIRISH PATWA HOUSE TO AGRWAL HOUSE IN W.NO. 14 (BUILDING SOR)	1. 06 माह 2. 3.89 लाख	1. 1500/- 2. 8000/-	28.05.2026
7	2026_UAD_506387	INVITEING RATE OF CONSTRUCTION MATERIAL FOR THE FINANCIAL YEAR 2026-27	1. 12 माह 2. 10.00 लाख	1. 2000/- 2. 20000/-	
8	2026_UAD_506388	Inviting Rate of all kinds of water moter winding and pumps repair works for Financial Year 2026-27	1. 12 माह 2. 03.00 लाख	1. 2000/- 2. 3000/-	
9	2026_UAD_506389	Inviting Rate of Printing of Flex and stationery items for Financial Year 2026-27	1. 12 माह 2. 03.50 लाख	1. 2000/- 2. 3500/-	
10	2026_UAD_506390	Inviting Rate of water material for Financial Year 2026-27	1. 12 माह 2. 15.00 लाख	1. 2000/- 2. 15000/-	
11	2026_UAD_507522	Inviting Rate of Tent items for Financial Year 2026-27	1. 12 माह 2. 5.00 लाख	1. 2000/- 2. 5000/-	
12	2026_UAD_507523	CONSTRUCTION OF PAVER BLOCK WORK IN W.NO. 06 (BUILDING SOR)	1. 12 माह 2. 0.95 लाख	1. 1000/- 2. 2000/-	

नोटः- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptender.gov.in की वेबसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद पेटलावद जिला-झाबुआ

संपादकीय

जन-सुरक्षा व पशु-कल्याण के बीच हो संतुलन

इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय निकायों द्वारा आवारा कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सर्वोच्च न्यायालय का हालिया निर्णय, बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। हाल ही में सामने आए केरल के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से सटे नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना, चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवारा कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल, विगत में भी इस संकट के कारगर समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तय की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नजर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार में परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है।

पिछले दिनों चंडीगढ़ से एक स्तब्धकारी घटना ने हर किसी संवेदनशील व्यक्ति को विचलित किया,जब एक अज्ञात व्यक्ति ने एक पिल्ले को धधकते तंदूर में फेंककर जिंदा जला दिया। ऐसे शर्मनाक कृत्य उस भयावह क्रूरता को उजागर करते हैं, जो सार्वजनिक चर्चाओं में उजागर नहीं होती। इस घटना ने इन जीवों की दयनीय स्थिति को ही उजागर किया। वहीं भूख से बिलबिलाते कुत्तों द्वारा कथित तौर पर अपने ही बच्चों को खाने के मामले भी शामिल हैं। शीर्ष अदालत की इस टिप्पणी से सहमत हुआ जा सकता है कि जानवरों के साथ मानवीय व्यवहार का मतलब नागरिकों की सुरक्षा की अनदेखी करना नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ ही जन सुरक्षा को पशु कल्याण की उपेक्षा का बहाना भी नहीं बनाया जा सकता है। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानवीय, जवाबदेह और प्रभावी आवारा पशु प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों , दोनों के हितों की रक्षा कर सके। हमेशा से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं। उन कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनके चलते कुत्ते अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे हैं। निश्चय ही बढ़ता तापमान बदलते मौसमों के प्रति संवेदनशील इन जीवों को बेचैन किए हुए है। भूख व आश्रय के अभाव से उपजे असुरक्षाबोध ने भी उन्हें आक्रामक बनाने में भूमिका निभायी है। ऐसे में पशु प्रेमी संगठनों और स्थानीय प्रशासन को मिलकर इस संकट का कारगर समाधान निकालना होगा। ये समाधान सिर्फ सरकार या स्थानीय निकायों के बूते होना संभव नहीं है। पशु प्रेमियों की बड़ी पहल के परिणाम बदलाव लाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

लोकतंत्र में नागरिक कॉकरोच, न्यायपालिका ने पहचाना?

देश में पिछले कुछ वर्षों में आंदोलनों, विरोध प्रदर्शनों और असहमति की आवाजों को शासन और प्रशासन द्वारा कठोरता के साथ दबाया जा रहा है। आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के लाठी डंडे, अश्रु गैस के बाद अब कठोर कानूनी धाराओं का उपयोग शुरू कर दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में एनएसए जैसी राष्ट्र विरोधी कार्यों वाली धाराओं का उपयोग प्रदर्शनकारियों, पत्रकारों, छात्रों, किसानों पर हो रहा है। लोकतंत्र की सेहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकारों का कारण बनती है। इस पर गंभीर बहस खड़ी हो गई है। छात्र, मजदूर, किसान, पत्रकार, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी जांच एजेंसियों के दमन और कठोर कानूनों की कार्रवाई से अछूता नहीं रहा। सरकारें चाहे केंद्र की हों या राज्यों की, सरकार के विरोध को ÷कानून-व्यवस्था÷ के स्थान पर अब राष्ट्र का विरोध मान लिया गया है। सरकार के निर्देश पर लंबे समय तक जेल में रखने की नीति जाँच एजेंसियाँ अपना रही हैं। इससे समाज के सभी वर्गों में असंतोष और सरकारों के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। अब यह गुस्सा और अविश्वास कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर भी दिखने लगा है। अदालतें सरकार के दबाव में जमानत जैसे मामलों में कई महीने और सालों तक लटकाकर रख रही हैं। सारी विधि व्यवस्था को न्यायपालिका स्वयं नजर अंदाज कर रही है। ऐसी स्थिति में अब न्यायपालिका के ऊपर आम नागरिकों को वह विश्वास नहीं रहा, जो पहले होता था। लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता है। नागरिकों को अपनी बात कहने, सरकार से सवाल पूछने और शांतिपूर्ण विरोध करने के अधिकार से लोकतंत्र मजबूत होता है। सरकारें नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती हैं। संविधान ने अभिव्यक्ति की

स्वतंत्रता और नागरिकों के विरोध के अधिकार को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है। पिछले कुछ वर्षों से आंदोलनकारियों पर गंभीर धाराएं लगाकर साजिशन महीनों या वर्षों तक जेल में रखा जा रहा है। बाद में पर्याप्त सबूत न मिलने पर वर्षों बाद आरोपी अदालत से बरी हो जाते हैं। तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कानून का उपयोग न्याय के लिए हो रहा है? सरकार से असहमति, आंदोलन, प्रदर्शन और विरोध को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का दुरूपयोग किया जा रहा है। हाल के वर्षों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं। लंबी हिरासत के बाद अदालतों में आरोपियों पर जो आरोप लगे थे, उससे संबंधित कोई तथ्य ही मुकदमे में नहीं था। अदालत में जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे। उसके बाद भी इन मामलों में कोई रोक नहीं लगी। ईडी, सीबीआई, पुलिस इत्यादि जांच एजेंसियां गंभीर धाराओं में आरोपियों को बंद करके जाँच एवं पूछताछ के नाम पर कई महीनो तक जेल में बंद रखती हैं। आरोपियों का ट्रायल भी शुरू नहीं करती हैं। जांच भी कई वर्षों तक पूर्ण नहीं होती है। इससे युवाओं, छात्रों और श्रमिक संगठनों एवं राजनीतिक दलों के बीच यह भावना मजबूत हुई है, कानूनों का दुरूपयोग सत्ता के लिये किया जा रहा है। न्याय मिलने में देरी भी एक तरह की सजा है। ÷तारीख पर तारीख÷ की व्यवस्था केवल अदालतों की प्रक्रिया नहीं रह गई, बल्कि यह आम नागरिक की पीड़ा, प्रताणना और निराशा का प्रतीक बन चुकी है। पेपर लीक जैसे मामलों ने युवाओं के गुस्से को बढ़ाया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट एवं अन्य परीक्षाओं में जब गड़बड़ी हुई थी, तब ऐसे मामले पर विचार करने से मना कर दिया। जब परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। आंदोलन करने वाले छात्रों पर पुलिस कठोर कार्रवाई करती है। न्यायपालिका से जब न्याय नहीं मिलता है, तब व्यवस्था के प्रति आम नागरिकों का विरोध बढ़ता है। लोकतंत्र में सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून लागू करना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास, कानून व्यवस्था पर बनाए रखना भी है। नागरिकों के अधिकार और भविष्य को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाना उनका पालन कराना, बिना किसी भेदभाव के और संवेदनशीलता के साथ नागरिकों के साथ व्यवहार करना होता है। इस पूरे परिदृश्य में न्यायपालिका की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। संविधान ने अदालतों को नागरिको के मौलिक एवं कानूनी अधिकारों का संरक्षक बनाया है। जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता लंबे समय तक दांव पर लगी हो। विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद हो, झूठे आरोप लगाकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा हो। तब न्यायपालिका से त्वरित, निष्पक्ष और संवेदनशील हस्तक्षेप की अपेक्षा होती है। यदि जांच एजेंसियों की कार्रवाई में त्रुटियां हैं, जांच एजेंसियों ने अपने अधिकारों का उल्लंघन किया हैं। किसी दबाव में साजिश के साथ जाँच एजेंसी ने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, वह त्वरित कार्यवाही कर न्याय करे। यह सच है, कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार का दायित्व है। हर आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शक्ति और अधिकार के साथ जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। इसलिए आवश्यक है, जांच एजेंसियां जब कठोर कानूनों का उपयोग करें ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को स्वमेव स्वतंत्र समीक्षा करनी चाहिए। आरोप के तहत जेल में बंद नागरिकों को भी जीने का अधिकार होता है। जेल में इन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में रखा जाता है। गलत कार्यवाही से आरोपी के सम्पूर्ण परिवार को खामियाजा भोगना पड़ता है। युवाओं का तो जीवन शुरू होने के पहिले बर्बाद कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के सबसे उच्च आसन पर बैठे जज द्वारा नागरिकों को कॉकरोच कहकर संबोधित किया जाए। ऐसी स्थिति में संविधान, लोकतंत्र, कानून का राज सब बेमानी है।

सनत जैन

संधियों के टिकाऊ ढांचे से डीलमेकिंग की डगमग डगर तक

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था संधियों और संस्थागत ढांचों पर टिकी थी। ब्रेटन वुड्स वित्तीय ढांचे से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक, सब कुछ नियम-आधारित था। यह व्यवस्था आदर्शवादी थी, जहां कानून और संधियां स्थायित्व देती थीं। लेकिन आज वह ढांचा बिखर चुका है। उसकी जगह आ गई है रियलपॉलिटिककृजहां स्थायी प्रतिबद्धताओं की जगह तात्कालिक सौदेबाजी और लचीले हितों का जाल है। साल 2024-25 में यूक्रेन युद्ध, गाजा संकट और ताइवान पर बढ़ते तनाव ने यह साफ कर दिया कि नियमों की दुनिया अब केवल कागज पर है।

दुनिया कठोर किलों से 'लाउंज कूटनीति' की ओर बढ़ी है। शीत युद्ध के नाटो और वारसा पैक्ट जैसी संस्थाएं कठोर थी, उनका उल्लंघन नहीं होता था। साल 1991 में सोवियत पतन के बाद उभरे जी-20, एससीओ और ब्रिक्स जैसे मंच जानबूझकर गैर-बाध्यकारी रखे गए। वर्ष 2024 की ब्रिक्स शिखर बैठक में सऊदी अरब और ईरान की सक्रिय भागीदारी ने दिखाया कि यह मंच अब 'आ ला कार्टे' कूटनीति का प्रतीक है। देश अपनी सुविधा से आते-जाते हैं। स्थायी प्रतिबद्धता नहीं, सुविधानुसार साझेदारी।

मौजूदा विश्व में व्यापार और युद्ध का अजीब संगम सामने है। इस नई व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण है निहित सहनशीलता। अमेरिका-चीन तनाव के बावजूद व्यापार जारी है। साल 2025 में अमेरिकी टेक कंपनियों ने चीन से 70 फीसदी से अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स आयात किए, जबकि वाशिंगटन बीजिंग को 'रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी' कहता रहा। पुरानी दुनिया में यह आत्मघाती होता, पर आज इसे आवश्यक लागत माना जाता है। यह विरोधाभास बताता है कि आपसी आर्थिक संबंध और रणनीतिक शत्रुता अब एक साथ चल रही हैं।

कूटनीति अब औपचारिक संधियों से नहीं, बल्कि फोन कॉल से तय होती है। मसलन, भारत-रूस तेल व्यापार पर अमेरिका का

टैरिफ-2024 में एक कॉल में 50 फीसदी से घटकर 18 फीसदी। यही दोहरा खेल अमेरिका रूस के साथ भी खेल रहा है-पुतिन से दोस्ताना संवाद और साथ ही यूक्रेन को गुप्त मदद। वर्ष 2025 में व्हाइट हाउस और क्रेमलिन के बीच हुई 'टेलीफोनिक डिप्लोमेसी' ने दिखाया कि मौखिक प्रतिबद्धताएं औपचारिक दस्तावेजों से अधिक प्रभावी हो गई हैं।

अमेरिका वैसे तो पाकिस्तान को आतंकवाद पर कोसता है, लेकिन 2024द्25 में उसे 2.5 अरब डॉलर की सहायता भी दी। भारत को सीमित रखने का यही तरीका है। चीन को रोकने के लिए भारत जरूरी है, फिर भी पाकिस्तान को मोहरे की तरह जीवित रखा जाता है। यह दोहरा रवैया बताता है कि सिद्धांतों की जगह केवल रणनीतिक उपयोगिता बची है। मित्र और मोहरा-दोनों एक साथ। नयी वैश्विक व्यवस्था के तहत दोहरे खेल की एक और मिसाल यह कि ताइवान को 2025 में 14 अरब डॉलर का हथियार पैकेज मिला, लेकिन इसे बीजिंग से सौदेबाजी का औजार बताया गया। सवाल है, क्या अमेरिका सैनिकों को 9,500 मील दूर भेजेगा? जब सुरक्षा गारंटी भी सौदेबाजी का हिस्सा बन जाए, तो पुरानी लक्ष्मण रेखाएं मिट जाती हैं। यह दिखाता है कि महाशक्ति भी अब अपने वादों को लाभ-हानि के तराजू पर तौल रही है।

नया दौर मिनिलैटरलिज्म का है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जो नियम-आधारित व्यवस्था का वास्तुकार था, अब खुद बहुपक्षवाद से पीछे हट चुका है। क्वाड, ऑकस और आई2यू2 जैसे छोटे, लचीले समूह उभरे हैं। साल 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस के तहत परमाणु पनडुब्बी समझौते को आगे बढ़ाया, जबकि आई2यू2 ने खाद्य सुरक्षा पर सहयोग किया। यह 'मिनिलैटरलिज्म' बताता है कि बड़ी संधियों की जगह छोटे-छोटे गठजोड़ ही भविष्य है।

भारत इस तरल यानी निरंतर बदलते माहौल में बहु-संरेखण का उदाहरण है। यह रणनीति मल्टी अलाइनमेंट की है। भारत ब्रिक्स और एससीओ में सक्रिय है, साथ ही क्वाड का स्तंभ भी। रूस से ऐतिहासिक संबंध बनाए रखते हुए अमेरिका के टैरिफ और पाकिस्तान नीति को संतुलित करता है। साल 2024द्25 में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ाया, साथ ही अमेरिका से रक्षा सहयोग भी गहरा किया। यह रणनीतिक हेजिंग भारत की संप्रभुता का नया मानक है।

प्रो. पूर्णेन्दु रंजन

बीते दौर के संस्थागत किले कठोर थे, पर टिकाऊ थे। वहीं आज की निहित सहनशीलता नाजुक है- किसी गलत गणना से ढह सकती है। साल 2024 में गाजा युद्ध और 2025 में यूक्रेन मोर्चे पर बढ़ते तनाव ने दिखाया कि मानवीय पीड़ा अब स्वीकार्य कीमत बन गई है। नीति-निर्माताओं के लिए चुनौती अब नए किलों के निर्माण की नहीं, बल्कि इस लेन-देनवादी राजनीति को दीर्घकालिक संयम में बदलने की है।

वर्तमान सौदेबाजी की दुनिया बिना किसी निश्चित दिशा के बह रही है। संधियों की स्याही से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के बदलते समीकरणों से संचालित हो रही है। यह व्यवस्था लचीली है, पर नाजुक भी। नीति-निर्माताओं के लिए असली चुनौती है-तात्कालिक सौदेबाजी को दीर्घकालिक स्थिरता में बदलना। जब तक यह नहीं होता, रियलपॉलिटिक का यह नया युग महाशक्तियों के दोहरे खेल और छोटे-छोटे क्लबों की राजनीति से ही परिभाषित रहेगा।

दिखावा नहीं हकीकत बने बदलाव की मुहिम

ऊर्जा संकट, बढ़ती ईंधन कीमतों और संसाधनों के संयमित उपयोग की जरूरत के बीच देश में वीआईपी संस्कृति को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील करते हुए अपने दौरों के दौरान काफिले में शामिल वाहनों की संख्या घटाने की पहल की है। इसके साथ ही उन्होंने अनावश्यक यात्राओं को कम करने और जहां संभव हो, डिजिटल माध्यमों तथा वर्चुअल बैठकों के अधिक उपयोग पर जोर दिया है। इसके बाद देशभर में नेताओं के बीच सादगी प्रदर्शित करने की मानो प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। कई नेता सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते दिखाई दिए, तो कई ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या घटाने की घोषणा की। विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिलों में कटौती की बात कही है।

लंबे समय से देश में वीआईपी संस्कृति को लेकर भारी असंतोष रहा है। आम लोगों के लिए ट्रैफिक रोक देना, दर्जनों गाड़ियां का काफिला, सायरन और भारी सुरक्षा व्यवस्था असमानता का प्रतीक माने जाते रहे हैं। ऐसे में यदि राजनीतिक नेतृत्व सादगी का संदेश देता है, तो यह स्वाभाविक रूप से लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए प्रधानमंत्री की पहल को राजनीतिक व्यवहार में बदलाव के संदेश के रूप में भी देखा जाना चाहिए।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। असल सवाल यह है कि क्या यह बदलाव वास्तविक है या केवल प्रतीकात्मक? जब कोई नेता सार्वजनिक परिवहन में सफर करता दिखाई देता है, तो उसके सुरक्षाकर्मी और सहयोगी अक्सर पीछे दूसरी गाड़ियों में चलते रहते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वास्तव में ईंधन की बचत हो रही है या केवल राजनीतिक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस देश में आम नागरिक पेट्रोल और डीजल के लिए सौ रुपये से अधिक चुका रहा है, वहां नेताओं के काफिलों पर लाखों रुपये का ईंधन खर्च होना जनता को स्वाभाविक रूप से अखरता है।

आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं अधिक जागरूक है। वह समझता है कि कौन-सा कदम वास्तविक सुधार की दिशा में है और कौन-सा केवल प्रचार के लिए किया गया प्रदर्शन है। आज राजनीति का बड़ा हिस्सा दृश्य संदेशों पर आधारित हो चुका है। चुनौती यह है कि यह संदेश व्यावहारिक बदलाव में कितना बदलता है।

यह भी सच है कि सुरक्षा को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं की सुरक्षा राष्ट्रीय जिम्मेदारी होती है। इसलिए केवल काफिला छोटा कर देना ही समाधान नहीं माना जा सकता। असली चुनौती यह है कि तकनीक और स्मार्ट सुरक्षा प्रबंधन के जरिये सुरक्षा और सादगी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

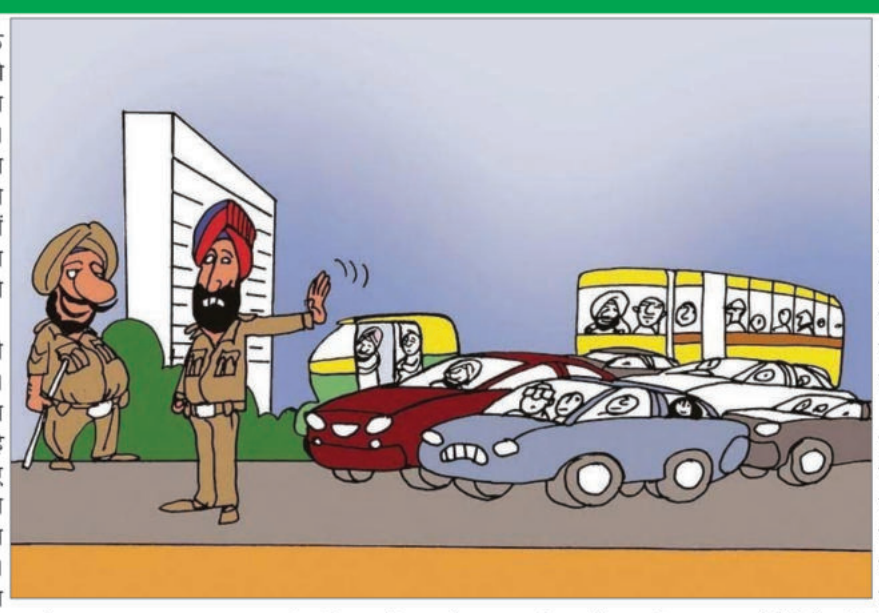

इस पूरे अभियान में एक और महत्वपूर्ण पक्ष नौकरशाही की भूमिका है। वीआईपी संस्कृति केवल नेताओं तक सीमित नहीं है। कई वरिष्ठ अधिकारियों के काफिले भी किसी मंत्री से कम नहीं होते। सरकारी बैठकों, निरीक्षणों और दौरों के दौरान बड़ी संख्या में गाड़ियां उपयोग में लाई जाती हैं। यदि ईंधन बचत की यह मुहिम सचमुच गंभीर है, तो पूरे प्रशासनिक ढांचे को इसके दायरे में लाना होगा।

ऊर्जा बचत के इस अभियान में डिजिटल कार्य संस्कृति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आज भी कई प्रशासनिक बैठकें और विभागीय चर्चाएं ऑनलाइन माध्यम से की जा सकती हैं। यदि मंत्री और अधिकारी अनावश्यक यात्राओं को कम कर डिजिटल बैठकों को बढ़ावा दें, तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि समय और सरकारी खर्च में भी भारी कमी आएगी।

यह मुद्दा केवल पेट्रोल और डीजल बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है, जिस पर हर साल अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च होती है। बड़े वीआईपी काफिले न केवल ईंधन की भारी खपत करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन बढ़ाकर पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं।

विकसित देशों में राजनीतिक सादगी को प्रशासनिक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां आम आदमी महंगे ईंधन से परेशान हैं, वहां वीआईपी संस्कृति पर नियंत्रण लोकतांत्रिक संवेदनशीलता का भी प्रश्न बन जाता है। जब कोई नेता सामान्य परिवहन का उपयोग करता दिखाई देता है, तो इससे सत्ता और जनता के बीच की मनोवैज्ञानिक दूरी कम होती है। हालांकि, यह भरोसा तभी मजबूत होगा, जब यह व्यवहार नियमित दिखे।

विवेक शर्मा

इस मुहिम को सफल बनाने के लिए केवल सत्तापक्ष ही नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना होगा। वीआईपी संस्कृति किसी एक दल की समस्या नहीं, बल्कि दशकों पुरानी व्यवस्था है, जिसे बदलने के लिए सामूहिक इच्छाशक्ति चाहिए। यदि काफिलों और अनावश्यक दौरों पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये बचा लिए जाएं, तो इस भारी-भरकम राशि का सीधा उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण की योजनाओं में किया जा सकता है। असल मायने में यही सच्चे और परिपक्व लोकतंत्र की पहचान होगी।

वीआईपी काफिलों पर होने वाला करोड़ों रुपये का खर्च अंततः करदाताओं की जेब से ही जाता है। अनावश्यक वाहनों और शक्ति प्रदर्शन पर सख्त रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से शामिल करने की दिशा में भी काम होना चाहिए। यदि वीआईपी संस्कृति पर लगाम लगाने की पहल ईमानदारी से लागू होती है, तो जनता और व्यवस्था के बीच भरोसा मजबूत होगा।

जिले की हर्बल मंडी की देशभार में धूम, कई राज्यों से पहुंच रहे किसान

फूल, कांटे, पत्ती, छिलके, बीज, छाल, जड़ सब के मिलते अच्छे दाम

नीमच।

मध्य प्रदेश के नीमच जिले की हर्बल मंडी औषधीय और मसाला फसलों के किसानों के लिए देशभर में बड़ा केंद्र बनकर उभरी है, जहां जड़ी-बूटियों को 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति क्विंटल तक के दाम मिल रहे हैं। बेहतर तुलाई, समय पर भुगतान और सरकारी सुविधाओं के कारण कई राज्यों के किसान भी अपनी उपज लेकर नीमच मंडी पहुंच रहे हैं।

जनसंपर्क अधिकारी क्रांतिदीप अलूने ने बताया कि यह हर्बल मंडी, देश की एक मात्र मंडी है जहां कांटे, फूल, पत्ती, छिलके, बीज, छाल, जड़ सब बिकते हैं। किसानों को विभिन्न औषधीय फसलों के 500 रूपये से लेकर 2 लाख रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल जाते हैं। नीमच मंडी की प्रसिद्धि देखते हुए गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान अपनी फसलें लेकर यहां आ रहे हैं।

उन्होंने बताया कि अप्रैल माह तक मंडी की भरपूर आवक बनी रहती है जो मई के आखरी सप्ताह तक कम होने लगती है। किसानों को निराश नहीं होना पड़ता। हर प्रकार की जड़ी-बूटी बिक जाती है। मुख्य मंडी प्रांगण में 16 शेड हैं। यह एक मात्र मंडी है जहां 40-50 प्रकार के औषधीय पौधों की खरीदी बोली लगाकर होती है। मसाला फसलों की खरीदी करने वाली देश की एक मात्र सबसे बड़ी मंडी है।

नीलेश पाटीदार नीमच के बड़े काश्तकार हैं। उनकी 45 एकड जमीन है। परिवार में 12 सदस्य हैं। वे पिछले दो-तीन सालों से मसाला फसलों की खेती कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इसबगोल, इरानी अकरकारा, चिरायता, आजवाइन, किनोवा, चियासीड, तुलसी बीज जैसी फसलों के बहुत अच्छे दाम मिल जाते हैं। लहसून के भी अच्छे दाम मिलते हैं। नीलेश को इस बात की प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव औषधीय फसलों के उत्पादन के लिये प्रोत्साहित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि सरकार जड़ी-बूटी की खेती के तौर-तरीकों के संबंध में अच्छी ट्रेनिंग दिलवायेगी तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। फिलहाल सरकार की ओर से हर जरूरी सहूलियतें मिल रही हैं। मदद सरकार की और मेहनत हमारी। जड़ी-बूटी उगाने वाले किसानों के लिये नीमच मंडी एक बड़ा सहारा है।

प्रह्लाद सिंह रतलाम जिले के आजमपुर डोडिया गांव में रहते हैं। उन्हें अश्वगंधा और अकरकारा बीज बेचने के अच्छे दाम मिले हें। मंडी में समय पर बोली लग जाती है और आसानी से फसल बिक जाती है। किसानों को जरा सी भी परेशानी नहीं होती। मंडी के सब लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है। सरकार ने हमारे जैसे छोटे और मझौले किसानों के लिए मंडी में अच्छी व्यवस्थाएं करा दी हैं।

पंचम सिंह भी इसी गांव के किसान है और आजवाइन, अश्वगंधा लेकर आते हैं। उन्हें तत्काल भुगतान हो जाता है। मंडी की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। वे बताते हैं कि अब मंडी की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई है। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र , उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसान लंबी दूर तय कर यहां माल जाते हैं। अच्छी तुलाई और अच्छे दाम और तत्काल भुगतान के कारण सब यहां आना पसंद करते हैं। इसबगोल, अश्वगंधा, कलौंजी, सतावारी, सफेद मूसली, केसर, सर्पगंधा, अकलकारा जड, जैसी फसलों के दाम ज्यादा है और मांग भी हमेशा बनी रहती है।

मंडी की विशेषताओं की चर्चा करते हुए मंडी सचिव उमेश बसेडिया शर्मा बताते हैं कि समय पर नीलामी, गुणवत्तापूर्ण तुलाई और भुगतान की व्यवस्था किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। किसानों के हित में निरंतर सुविधाएं बढाई जा रही हैं। वित्तीय प्रबंधन निरंतर सुधरा है। वर्ष 2024-25 में 64.16 लाख क्विंटल और 2025-26 में 72.40 क्विंटल आवक हुई थी। वे बताते हैं कि मंडी ने किसानों के हित की सभी व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरूस्त कर दिया है। राष्ट्रीय पादप बोर्ड ने साढे पांच करोड़ रूपये का अनुदान भी मंडी की अधोसंरचनात्मक गतिविधियों के लिये उपलब्ध कराया है। इलेक्ट्रानिक नाप-तौल और सीधे व्यापारियों के गोडाउन में पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। यह मंडी प्रांगण 10.9 हेक्टेयर में फैला है। करीब 1100 लाइसेंसधारी व्यापारी इससे जुडे हैं और 150 से ज्यादा तुलावटी उपलब्ध रहते हैं।

औषधीय फसलों के उत्पादन में देश में आगे मप्र

मध्य प्रदेश औषधीय फसलों के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। प्रदेश में 46 हजार 837 हैक्टेयर क्षेत्र में औषधीय फसलों ईसबगोल, सफेद मुसली, कोलियस व अन्य फसलों की खेती की जा रही है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश में लगभग सवा लाख मीट्रिक टन औषधीय फसलों का उत्पादन हुआ है। देश और विदेश में औषधीय फसलों की बढ़ती मांग से किसान इन फसलों की ओर आकर्षित हुए हैं।

गौरतलब है कि देश में औषधीय फसलों का 44 प्रतिशत हिस्सा मध्यप्रदेश में उत्पादित होता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के साथ किसानों को अनुदान और अन्य सहूलियतें दी जा रही है। औषधीय पौधों की खेती से किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक का अनुदान देती है। औषधीय पौधों की खेती और संग्रह से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रदेश में प्रमुख रूप से अश्वगंधा, सफेद मूसली, गिलोय, तुलसी और कोलियस जैसी कई औषधीय फसलों का उत्पादन होता है।

नर्सिंग कॉलेज में कथित फर्जी जीएसटी वसूली में लोकायुक्त की कार्रवाई

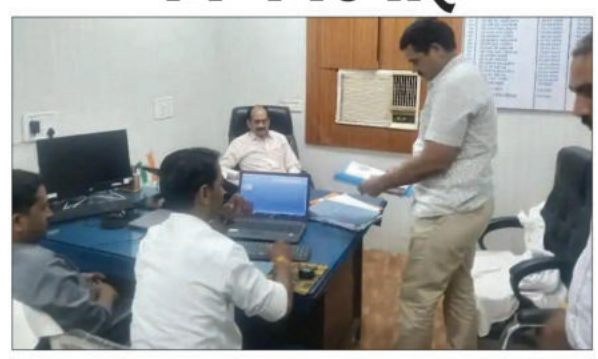

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले के शासकीय नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं के स्टायफंड और मेस भुगतान में कथित अनियमितताओं के मामले ने तूल पकड़ लिया है। फर्जी जीएसटी वसूली, बिना टेंडर ठेका देने और छात्राओं के खातों से सीधे राशि ट्रांसफर किए जाने की शिकायतों के बाद लोकायुक्त संगठन उज्जैन की टीम ने मंगलवार को सीएमएचओ कार्यालय में जांच कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने करीब चार घंटे तक दस्तावेजों और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की। कार्रवाई के दौरान मेस भुगतान, स्टायफंड और बैंक ट्रांजैक्शन से संबंधित कई महत्वपूर्ण फाइलें और दस्तावेज जब्त किए गए। कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप की स्थिति रही।

मामले की शिकायत जनवरी 2026 में विधायक प्रतिनिधि मनोहर नाहटा द्वारा लोकायुक्त उज्जैन में की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शासकीय नर्सिंग कॉलेज की 57 छात्राओं के स्टायफंड से जुड़ी राशि में अनियमितता की गई।

आरोप है कि छात्राओं के मेस का मासिक खर्च 2200 रुपये निर्धारित होने के बावजूद इसे बढ़ाकर 4400 रुपये कर दिया गया। शिकायत के मुताबिक भोजन पर 100 प्रतिशत जीएसटी लगाने का हवाला दिया गया, जबकि ऐसी कोई कर व्यवस्था लागू नहीं है। मामले में स्काईबुल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड नामक ठेकेदार कंपनी का भी उल्लेख किया गया है।

शिकायत में यह भी कहा गया कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण नियमों का उल्लंघन करते हुए छात्राओं के खातों में राशि भेजने के बजाय करीब 8.06 लाख रुपये सीधे ठेकेदार के खाते में ट्रांसफर किए गए, जबकि वास्तविक बिल लगभग 3.76 लाख रुपये का बताया गया। इस आधार पर अतिरिक्त राशि वसूली और वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार जब्त दस्तावेजों और बैंक लेनदेन की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में तत्कालीन सीएमएचओ और संबंधित अकाउंट शाखा से भी पूछताछ की गई है।

किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

माही की गूंज, रतलाम।

जिले में किसानों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर जिला किसान कांग्रेस कमेटी रतलाम ग्रामीण और आदिवासी कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया।प्रदर्शन के दौरान किसान नेता राजेश पुरोहित तपती धूप में प्रतीकात्मक विरोध जताते हुए लेटकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं, कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताने के लिए बिल्ली भी साथ लेकर पहुंचे और प्रशासन को ष्भीगी बिल्लीष् की संज्ञा दी।

प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुबह से ही कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया था। मुख्य गेट पर बैरिकेड्स लगाए गए थे। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान हाथों में झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए परिसर में पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच बैरिकेड्स को लेकर हल्की धक्का-मुक्की की स्थिति भी बनी। कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष राजेश भरावा ने आरोप लगाया कि जिले में गेहूं उपार्जन और खाद वितरण जैसी समस्याओं पर प्रशासन पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है।

कुछ देर बाद एडीएम डॉ. शालिनी श्रीवास्तव मौके पर पहुंचीं। कांग्रेस नेताओं ने उन्हें राज्यपाल और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन सौंपने के बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाकर विरोध जताया गया। इस दौरान पुलिस ने पुतला हटाने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर के लिए प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच छीना-झपटी की स्थिति बनी। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर भीड़ को हटाया और आग बुझाई।

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गेहूं उपार्जन केंद्रों पर किसानों को लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि स्लॉट बुकिंग, खाद वितरण और फार्मर आईडी जैसी व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है। साथ ही, किसानों और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी कार्रवाई की मांग उठाई गई।

प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष हर्षविजय गेहलोत, किसान नेता डीपी धाकड़, आदिवासी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष किशन सिंगाड़ सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे।

जिले में खाद का पर्याप्त भंडारण

माही की गूंज, रतलाम।

उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास आर.के.सिंह ने बताया कि जिले में 16 मई को ई विकास पोर्टल के माध्यम से 264 टोकन जनरेट किये गये जिसमें किसानों द्वारा यूरिया 14.310, डी.ए.पी. 3.25, एन.पी.के. 6.30, टी.एस.पी. 0.55, एस.एस.पी. 3.45, तथा एम.ओ.पी. 0.60 मीट्रिक टन का वितरण होकर किसानों को प्राप्त हुआ है।

इसी प्रकार 01 अप्रैल से 16 मई तक कुल 14117 टोकन किसानों द्वारा जनरेट किये गये है तथा 5694 किसानों द्वारा उर्वरकों का क्रय किया गया है। साथ ही 01 अप्रैल से 16 मई तक कुल विकास पोर्टल के माध्यम से यूरिया 751.165, डी.ए.पी. टी.एस.पी 151.70, एन.पी.के. 169.200, एस.एस.पी. 147.650, तथा एम.ओ.पी. 15.300 मीट्रिक टन का वितरण किसानों द्वारा किया जा चुका है। जिले में पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का भण्डारण उपलब्ध है। रविवार को जिले में यूरिया 5725.48, डी.ए.पी. टी.एस.पी 2763.65, एन.पी.के. 4563.85, एस.एस.पी. 4199.70, तथा एम.ओ.पी. 247.25 मीट्रिक टन इस प्रकार कुल 17499.73 मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता है।

संयुक्त निरीक्षण दल

उप संचालक किसान कल?याण तथा कृषि विकास आर.के.सिंह, निरीक्षक एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वाय.एस.निनामा तथा मास्टर ट्रेनर आनंदीलाल पाटीदार द्वारा सैलाना विकासखंड की उर्वरक फर्मों का गत दिनों निरीक्षण किया गया। किसानों को सुगमता पूर्वक ई-टोकन जनरेट होकर उर्वरक प्राप्त हो रहा है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। किसान भाइयों से अपील की जाती है कि यदि ई-टोकन जनरेट करने में कोई समस्या आए तो वे अपने क्षेत्र के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या नजदीकी कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित करें- सीईओ जैन

माही की गूंज, मंदसौर।

जिले में मंगलवार को जिला पोषण एवं जिला स्वास्थ्य समिति की संयुक्त बैठक जिला पंचायत सीईओ अनुकूल जैन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए सीईओ जैन ने निर्देश दिए कि सभी संबंधित पोर्टलों पर डेटा एंट्री का कार्य शत-प्रतिशत एवं समय पर किया जाए।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले नाश्ते एवं भोजन वितरण की जानकारी प्रतिदिन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित संचालन सुनिश्चित किया जाए तथा हितग्राहियों को प्रदाय की जा रही सेवाओं की निरंतर समीक्षा की जाए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नवीन हितग्राही पंजीयन करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सभी बच्चों की ह्यअपारह्ल एवं ह्यआभाह्ल आईडी अनिवार्य रूप से बनाए जाने के निर्देश दिए गए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों की समग्र आईडी तैयार करने को कहा गया।

सीईओ जैन ने कहा कि यदि मैदानी स्तर पर कोई नवाचार या नया प्रयोग किया जा रहा है तो उसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अन्य क्षेत्रों को भी उससे प्रेरणा मिल सके। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। टेक होम राशन के शत-प्रतिशत वितरण पर भी विशेष जोर दिया गया। मैदानी मॉनिटरिंग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नव नियुक्त पर्यवेक्षकों को अपने-अपने सेक्टर के समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित भ्रमण एवं निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती बच्चों को आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं 14 दिवस की प्रोत्साहन राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम को अस्पतालों में ओपीडी सेवाओं पर विशेष ध्यान देने, टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत लगातार विशेष अभियान चलाने तथा आईडीएसपी कार्यक्रम की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।

यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बसों में सामने आई बड़ी लापरवाही

माही की गूंज, शाजापुर।

जिले के मक्सी क्षेत्र में आगरा-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर होटल के बाहर खड़ी एसी बस में लगी आग में चार वर्षीय मासूम जिंदा जल गया। बच्चे के पिता के अनुसार बस में अग्निशमन यंत्र, चिकित्सा सुविधा या इमरजेंसी द्वार नही था। जिसके कारण बच्चे अंदर ही फंसा रह गया और उसकी जलने से मौत हो गई। वे इसे हादसा नही हत्या करार देते हैं।

कहते हैं बस संचालक, चालक और सरकारी महकमा इसके लिए जिम्मेदार है। हादसे के बाद भी प्रभावी कार्रवाई नही होना जिम्मेदारों की सक्रियता पर सवाल खड़े कर रहा है। इस हादसे के बाद नईदुनिया टीम ने जिले में संचालित यात्री बसों की स्थिति देखी। 18 मई के अंक में बसों की स्थिति को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की। जिस पर यातायात पुलिस ने यात्री बसों की चेकिंग कर चालानी कार्रवाई करने की बात कहीं।

19 मई को जिला परिवहन अधिकारी रीना किराड़े भी रोड पर उतरी और यातायात पुलिस के साथ मिलकर यात्री बसों की चेकिंग की। इस दौरान भी बसों में सुरक्षा उपाय, यात्री सुविधाओं की अनदेखी किए जाने की स्थिति सामने आइ। हालांकि इसके बावजूद यात्री बसें अभी भी मनमाने आलम में ही चल रही हैं। अधिकांश बसों में सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जा रही है।

लगातार सामने आ रहीं घटना

जिले में वाहनों में आग लगने की घटना लगातार सामने आ रही हैं। दो वर्ष में यात्री बसों में आग लगने की चार घटना हो चुकी हैं। तीन घटना में सिर्फ बस जलकर खाक हुईं किंतु शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात मक्सी के पास होटल के बाहर खड़ी बस में लगी आग में चार वर्षीय बच्चा अनय पुत्र अभिषेक जैन जिंदा जल गया।

इसके पहले सनकोटा में गत वर्ष होटल के बाहर एक वर्ष में और उसके बाद चलती बस में आग लगी। वहीं इस वर्ष अप्रैल माह में बरातियों से भरी बस में आग लगी और फिर चौथी घटना मक्सी में हुई। सभी घटनाओं में सुरक्षा उपाय और नियमों की अनदेखी सामने आई। जो अब भी जारी है।

नियमों का पालन कराना चाहिए

वहीं उक्त मामले में शाजापुर-देवास सांसद महेंद्रसिंह सोलंकी ने कहा कि, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना परिवहन और यातायात पुलिस अमला, जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। संबंधितों को अभियान चलाकर प्रभारी कार्रवाई कर यात्री वाहनों में नियमों का पालन कराना चाहिए। साथ ही मक्सी में बस में लगी आग में बच्चे की जलने से मौत की घटना दुखद है। इस मामले में भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।

ऑन लाइन दवा बिक्री के विरोध में जिलेभर के मेडिकल स्टोर बंद

माही की गूंज, खंडवा।

ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के विरोध में बुधवार को खंडवा जिले के लगभग 450 मेडिकल स्टोर बंद रहे। जिले के केमिस्टों ने एक दिवसीय सांकेतिक बंद रखकर सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखीं। दोपहर में खंडवा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे और डिप्टी कलेक्टर दीक्षा भगोरे को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ने भी आंदोलन को समर्थन दिया।

एसोसिएशन अध्यक्ष गोवर्धन गोलानी ने बताया कि ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की अवैध बिक्री लगातार बढ़ रही है। फर्जी ई-पर्चियों के आधार पर दवा वितरण, बिना डॉक्टर की सलाह के घर-घर दवाएं पहुंचाना और भारी छूट देकर बिक्री करना मरीजों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है। इससे छोटे दवा व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है।

केमिस्टों ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 में ऑनलाइन दवा बिक्री को लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, फिर भी कई ऑनलाइन कंपनियां खुले तौर पर दवाओं की बिक्री कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां अधिसूचनाओं का गलत फायदा उठाकर अनियंत्रित तरीके से दवा वितरण कर रही हैं।

ज्ञापन में प्रशासन से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने, बिना सत्यापित ई-पर्चियों पर दवा देने पर कार्रवाई करने और अत्यधिक छूट देने वाली कंपनियों पर नियंत्रण लगाने की मांग की गई।

केमिस्ट संगठनों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान दवा व्यापारियों ने लगातार सेवाएं देकर लोगों तक दवाएं पहुंचाईं। ऐसे में सरकार को मरीजों की सुरक्षा और स्थानीय व्यापारियों के हित में जल्द निर्णय लेना चाहिए।

खरगोन में विरोध स्वरूप बंद रहे 600 से अधिक मेडिकल

माही की गूंज, खरगोन।

ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में बुधवार को देशव्यापी हड़ताल के तहत खरगोन जिले में दवा कारोबार पूरी तरह प्रभावित रहा। जिलेभर में 600 से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहे। जिला केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े दवा व्यवसायी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया।

व्यवसायियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन दवा कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिना उचित निगरानी के हो रही ऑनलाइन दवा बिक्री जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है। इससे स्थानीय केमिस्टों के साथ-साथ आम लोगों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऑनलाइन माध्यम से नकली दवाओं की बिक्री भी बढ़ रही है, जिससे देशभर के लाखों दवा व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।

जिला केमिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष लोकेंद्र छाजेड़ और शहर अध्यक्ष शैलेश महाजन ने कहा कि दवा कारोबार पूरी तरह नियमों के तहत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केमिस्ट सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर दवा वितरण कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन दवा बिक्री पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है।

ई-फार्मेसी के विरोध में मेडिकल स्टोर बंद, केमिस्टों ने जताया विरोध

माही की गूंज, बड़वानी।

ई-फार्मेसी और त्वरित दवा वितरण एप्स के विरोध में बुधवार को बड़वानी जिले के करीब 400 मेडिकल स्टोर बंद रहे। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स द्वारा बुलाए गए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा था। मेडिकल स्टोर बंद रहने से मरीजों और उनके परिजनों को दवाइयां खरीदने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

दवा व्यापारियों ने ऑनलाइन माध्यम से हो रही दवा बिक्री को जनस्वास्थ्य और पारंपरिक दवा कारोबार के लिए गंभीर खतरा बताया। पश्चिम निमाड़ केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव बलराम यादव ने कहा कि ई-फार्मेसी और त्वरित दवा वितरण एप्स बिना स्पष्ट और सख्त नियमों के संचालित हो रहे हैं, जिससे छोटे मेडिकल स्टोरों का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

केमिस्ट संगठनों का आरोप है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एंटीबायोटिक, आदत बनाने वाली दवाइयां और अन्य नियंत्रित औषधियां भी आसानी से उपलब्ध कराई जा रही हैं। कई मामलों में बिना सही चिकित्सकीय पर्चे की जांच किए दवाइयां बेची जा रही हैं और फर्जी पर्चियों का उपयोग भी किया जा रहा है।

दवा व्यापारियों ने कहा कि यह केवल कारोबार बचाने का मामला नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। उनका कहना है कि दवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध मरीज की जान और स्वास्थ्य से होता है। वर्तमान व्यवस्था में योग्य चिकित्सक और पंजीकृत फार्मासिस्ट की निगरानी में ही दवा वितरण किया जाता है, जबकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस व्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं। एसोसिएशन ने यह भी चिंता जताई कि एक ही चिकित्सकीय पर्चे का कई बार उपयोग किया जा रहा है और कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सत्यापन योग्य नहीं होने वाले पर्चों के आधार पर भी दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके अलावा मरीज और पंजीकृत फार्मासिस्ट के बीच प्रत्यक्ष संवाद नहीं होने से गलत दवा वितरण का खतरा बढ़ रहा है।

संगठन की मुख्य मांग है कि ई-फार्मेसी पर भी वही सख्त नियम लागू किए जाएं जो पारंपरिक मेडिकल स्टोरों पर लागू होते हैं। केमिस्ट संगठनों ने केंद्र और राज्य सरकार से अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने तथा कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा अपनाई जा रही अत्यधिक छूट नीति पर नियंत्रण करने की मांग की है। पश्चिम निमाड़ केमिस्ट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन तथा राष्ट्रीय संगठन एआईओसीडी से संबद्ध है। संगठन के अनुसार देशभर में 12 लाख से अधिक केमिस्ट और वितरक इससे जुड़े हुए हैं। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से सरकार से इस संबंध में कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे लाखों दवा व्यापारियों की आजीविका प्रभावित हो रही है।

इंदिरा सागर सिंचाई नहरों की बदहाली से किसानों की चिंता बढ़ी

माही की गूंज, बड़वानी।

इंदिरा सागर परियोजना के तहत 16 मई को मुख्य नहर में पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके अगले आठ से दस दिनों में बड़वानी पहुंचने की संभावना है। हालांकि खेतों तक पानी पहुंचाने वाली माइनर और सब-माइनर नहरों की खराब स्थिति किसानों की चिंता बढ़ा रही है।

बीते कई वर्षों से नहरों की नियमित सफाई और मरम्मत नहीं होने के कारण उनमें गाद भर गई है और कई जगह झाड़ियां उग आई हैं। इससे पानी के रिसाव और बर्बादी की आशंका बनी हुई है। सजवानी, रेहगुन, सुराना और तलवाड़ा बुजुर्ग सहित कई गांवों के किसानों ने नहरों की जर्जर स्थिति को लेकर नाराजगी जताई है।

किसानों का कहना है कि नहरें कई स्थानों पर संकरी हो चुकी हैं और दीवारों में दरारें आने से खेतों तक पहुंचने से पहले ही पानी बह जाने का खतरा है। भारतीय किसान संघ के जिला सदस्य धर्मेंद्र राठौर ने आरोप लगाया कि विभाग हर वर्ष केवल आश्वासन देता है, जबकि जमीनी स्तर पर सुधार कार्य नहीं हो पाता।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार नहरों के सुधार के लिए शासन को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। इंदिरा सागर परियोजना के सहायक अभियंता डीके गोरी ने बताया कि मुख्य अभियंता की नियुक्ति नहीं होने से फाइलें लंबित थीं। अब बजट स्वीकृत होने के बाद निविदा प्रक्रिया के जरिए मरम्मत कार्य कराया जाएगा।

मुख्य नहर में पानी छोड़े जाने के बाद किसानों को आशंका है कि मरम्मत और सफाई का कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाएगा। किसानों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो इस सीजन में भी फसलों को पर्याप्त सिंचाई का लाभ नहीं मिल सकेगा।

दो सड़क हादसों में चार घायल, एक युवक की हालत गंभीर

माही की गूंज, बड़वानी।

बुधवार देर रात हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोग घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। एक हादसा शहर के सांवरिया मंदिर के सामने हुआ, जबकि दूसरा राजघाट रोड स्थित सर्किट हाउस के पास हुआ। दोनों घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखने को मिली।

पहला हादसा सांवरिया मंदिर के सामने उस समय हुआ जब मंदिर दर्शन कर लौट रहे अर्चना, निलेश, हंसिका और मंथन मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी रूपेश मायरिया के अनुसार इसी दौरान गलत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे एक छोटा हाथी वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़ लगाई और 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे और मुख्य मार्गों पर कई वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं करते। गलत दिशा में वाहन चलाना, तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग करना आम बात हो गई है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

दूसरा हादसा राजघाट रोड स्थित सर्किट हाउस के पास हुआ। कुकरा बसाहट निवासी संजय वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में संचालित ईंट भट्टों से निकलने वाला घना धुआं सड़क पर फैल जाता है, जिससे वाहन चालकों को सामने का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी दौरान मछली पकड़कर बाइक से घर लौट रहे 17 वर्षीय अखिलेश केवट दुर्घटना का शिकार हो गए। हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत साईं अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

क्षेत्र के रहवासियों ने बताया कि राजघाट रोड पर रेत और मिट्टी से भरे डंपरों की लगातार आवाजाही रहती है। भारी वाहनों के गुजरने से सड़क पर धूल का गुबार बना रहता है, जिससे दृश्यता प्रभावित होती है और हादसों की संभावना बढ़ जाती है। लोगों का आरोप है कि संबंधित विभागों द्वारा कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़क किनारे चल रहे ईंट भट्टों और भारी वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण किया जाए। साथ ही सड़क सुरक्षा के लिए नियमित निगरानी, यातायात व्यवस्था में सुधार और गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

अस्पताल के ड्यूटी डॉक्टर ने बताया कि दोनों हादसों में घायल लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद भर्ती किया गया है। चिकित्सकों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रख रही है। एक घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है।

50 एकड़ में तैयार होंगी मछलियां, प्रदेश का पहला एकीकृत मत्स्य पालन पार्क

माही की गूंज, खंडवा।

प्रदेश का पहला एकीकृत मत्स्य पालन एक्वा पार्क जिले के खालवा ब्लॉक के रोशनी गांव में तैयार किया गया है। करीब 50 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस पार्क में मछली बीजों को शेड के नीचे बनाए गए 14 जैविक फ्लॉक टैंकों में छोड़ा जाएगा। छह से आठ माह के भीतर बंगाल से लाई गई तिलापिया प्रजाति की मछलियां एक से सवा किलो तक वजन की हो जाएंगी।

नीति आयोग और शासन की 10 विभिन्न योजनाओं के समन्वय से तैयार किए गए इस अत्याधुनिक पार्क का संचालन 16 आदिवासी महिला स्व-सहायता समूहों की 160 सदस्य करेंगी। इससे क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

बुधवार को पार्क के टैंकों में करीब ढाई लाख मछली बीज डालकर परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा। अगले आठ से दस महीनों में यहां प्रतिमाह लगभग 30 टन और सालाना करीब 360 टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए हर माह लगभग 30 लाख रुपए तथा सालाना करीब 3 करोड़ 60 लाख रुपए के कारोबार का अनुमान है। इससे क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

एकीकृत मत्स्य पालन एक्वा पार्क में मछलियों के पालन के लिए शेड के नीचे 14 जैविक फ्लॉक टैंक बनाए गए हैं। सबसे पहले इनमें मछली बीज डाले जाएंगे। मछलियों का आकार बढ़ने पर उनकी ग्रेडिंग कर उन्हें रिवर्स एक्वा सिस्टम टैंकों में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें जैविक फ्लॉक तालाबों में छोड़ा जाएगा। मछलियों के और बड़े होने पर उन्हें 1200 घन मीटर क्षमता वाले आवलिया डेम के बैकवॉटर क्षेत्र में लगाए गए 120 आधुनिक पिंजरों में डाला जाएगा, जहां उनका व्यावसायिक स्तर पर पालन किया जाएगा।

क्या है भारत मे विद्या व विद्यार्थियो का भविष्य

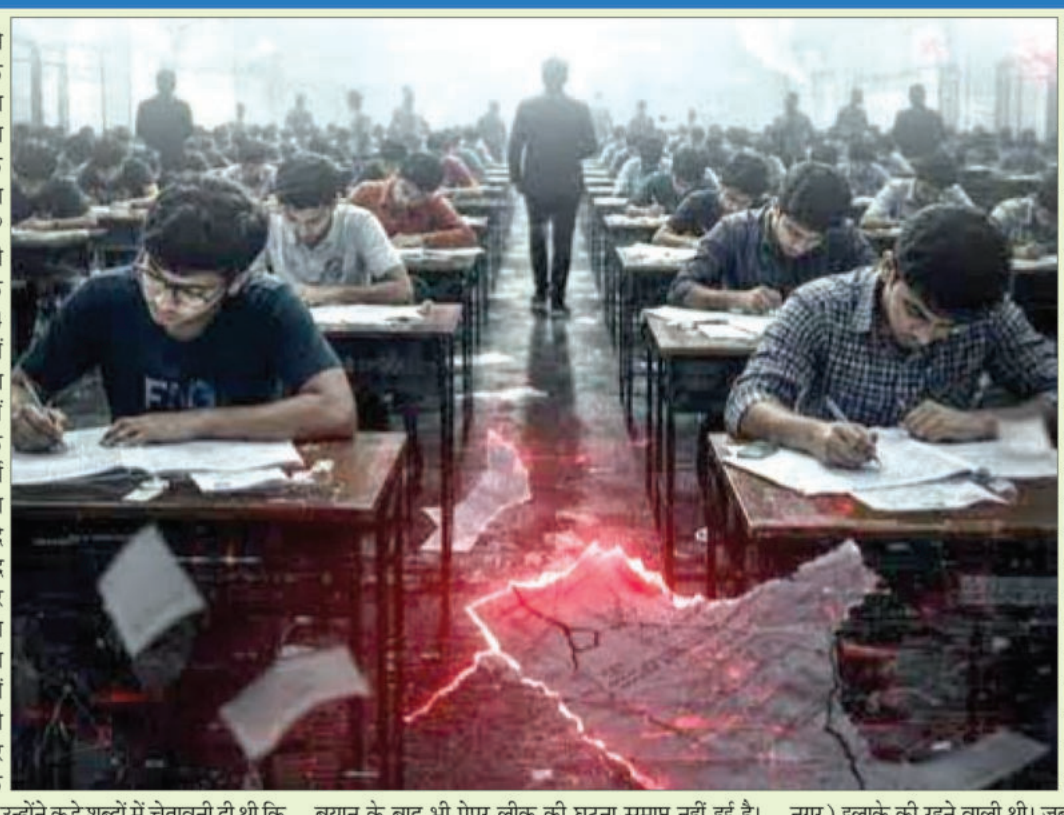

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारा देश से की जा रही मन की बात के 131वें एपिसोड में गत 22 फरवरी 2026 को छात्रों से परीक्षा पे चर्चा की थी। अपने इस संवाद कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिये गये उपदेशों में कहा कि अंकों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। शिक्षा जीवन को संवारने का एक माध्यम है, जबकि परीक्षा केवल आत्म-मूल्यांकन का जरिया है। उन्होंने छात्रों से परीक्षा को किसी बड़े बोझ या हौवे के रूप में देखने के बजाय इसे एक उत्सव की तरह मनाने की अपील की थी । पढ़ाई, आराम, शारीरिक खेलकूद और अपने शौक के बीच एक सही संतुलन बनाने को जरूरी बताया था। मोदी ने छात्रों को सलाह दी थी कि कुछ छात्र रात में पढ़ना पसंद करते हैं तो कुछ सुबह जल्दी, अपनी इसी मूल शैली पर विश्वास रखें। उन्होंने छात्रों को यह सलाह भी दी कि वे अपने मन की चिंताओं को अपने माता-पिता और परिवार के साथ खुलकर साझा करें, जिससे मानसिक तनाव कम होता है। अभिभावकों को सलाह देते हुये उन्होंने कहा था कि माता-पिता को बच्चों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध विशिष्ट करियर चुनने का दबाव नहीं बनाना चाहिए। हर बच्चा अपने आप में अनूठा होता है। इसी तरह उन्होंने शिक्षकों को भी सलाह दी कि उन्हें छात्रों की सीखने की गति को समझना चाहिए और उनके लिए ऐसे लक्ष्य तय करने चाहिए जो पहुंच में हों लेकिन जिन्हें प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े।

प्रधानमंत्री के उपरोक्त कथन में यह बात पूरी तरह विरोधाभासी है कि अंकों से किसी की योग्यता तय नहीं होती। क्योंकि आज के दौर में एडमिशन, वरीयता सूची, श्रेणी निर्धारण, चयन आदि हर जगह अंक प्रतिशत की ही होड़ लगी हुई है। परन्तु प्रधानमंत्री ने इन्हीं छात्रों को कभी यह नहीं बताया कि यदि आपकी जी तोड़ मेहनतों के बाद परीक्षा के पर्चे लीक हो जायें व परीक्षा ही स्थगित कर दी जाये तो आखिर छात्रों को ऐसे सदमे से कैसे उबरना चाहिये। और जो छात्र इस कुप्रबंधन का शिकार होकर किसी कारणवश पुनः परीक्षा में बैठने योग्य न रह सके और इसी कारण उसका जीवन व भविष्य चौपट हो जाये उस छात्र को उसके अभिभावकों को या फिर सरकार अथवा इस दुर्व्यवस्था के जिम्मेदारों को क्या करना चाहिये? हालाँकि प्रधानमंत्री मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर जुलाई 2024 में संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना आधिकारिक बयान दे चुके है। उन्होंने संसद में देश के हर छात्र और नौजवान को भरोसा दिलाते हुए कहा था कि सरकार परीक्षाओं में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों और पेपर लीक को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है। उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी आरोपी या माफिया को कतई बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने परीक्षा प्रणाली और पूरे सिस्टम को पुख्ता व पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा युद्ध स्तर कदम उठाने की बात कही थी।

परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद भी पेपर लीक की घटना समाप्त नहीं हुई है। अभी इसी मई 2026 में आयोजित हुई नीट परीक्षा को पेपर लीक विवादों और धांधली की शिकायतों के बाद सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है और अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इस परीक्षा में 22, 05, 035 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। आज इन 22 लाख से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। पेपर लीक और उसे रद्द किए जाने से उपजे मानसिक तनाव के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों से कम से कम 4 छात्रों द्वारा आत्महत्या करने की दुखद खबरें सामने आई हैं। इनमें एक छात्र प्रदीप मेघवाल (उम्र 22 वर्ष) राजस्थान के झुंझुनूं जिले का था जबकि ऋतिक मिश्रा (उम्र 21 वर्ष) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी का निवासी था। यह ऋतिक का नीट परीक्षा का तीसरा प्रयास था और वे इस बार चयन को लेकर बेहद आश्वस्त था। परीक्षा रद्द होने की खबर से वह मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया था। इसी तरह 20 वर्षीया अंशिका दिल्ली के आजादपुर (आदर्श नगर) इलाके की रहने वाली थी। जबकि 17 वर्षीय सिद्धांत हेगड़े दक्षिण गोवा के कटोरिम का रहने वाला था। हेगड़े पेपर लीक की घटना से इतना आहत था कि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वह अब और प्रतियोगी परीक्षाएं नहीं देना चाहता।

एक तरफ तो नीट पेपर लीक के चलते 22 लाख से अधिक मेधावी छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है साथ ही देश में गत 10 वर्षों के दौरान भारत में लगभग एक लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। तो दूसरी तरफलाखों रूपये खर्च कर अयोग्य व निठल्ले लोग डॉक्टर्स की फर्जी डिग्री लेकर मरीजों की जान से खिलवाड़ करते फिर रहे हैं। पिछले दिनों भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश के दमोह जिले से पुलिस ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे सरकारी संजीवनी क्लीनिकों में डठठै की फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे 3 नकली डॉक्टरों को गिरफ्तार किया। ग्वालियर निवासी कुमार सानू शाक्य, देवेंद्र चौधरी और जबलपुर के पल्लव जैन ने गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी एमबीबीएस की डिग्रियां और मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 8,00,000 से 10,00,000 तक में खरीदे थे। दमोह के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जब दस्तावेजों का वेरिफिकेशन कराया गया, तो डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर पूरी तरह फर्जी पाए गए।

निर्मल रानी

सवाल यह है कि जब नीट जैसी अति महत्वपूर्ण परीक्षा के इतिहास में अब तक 5 बार बड़े स्तर पर पेपर लीक और धांधली के गंभीर मामले सामने आ चुके हों जिनकी आधिकारिक जांच या अदालती कार्यवाही भी हुई हो। इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग राज्यों में 70 से अधिक परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हों जिससे करोड़ों मेघावी छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है उधर 8 - 10 लाख रुपये में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की जा रही हो ऐसे में भारत में विद्या व विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में आसानी से सोचा जा सकता है।

अतिक्रमण मामले में प्रशासनिक चुप्पी

माही की गूंज, शुजालपुर।

शाजापुर जिले के रानो गंज क्षेत्र में ऊष्मा पेट्रोलियम के सामने स्थित आवासीय भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला अब प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कई बार कलेक्टर, एसडीएम और जनसुनवाई में आवेदन दिए गए, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने केवल आश्वासन देकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्षेत्र में चर्चा है कि, एसडीएम स्तर से अतिक्रमण हटाने को लेकर मौखिक आदेश भी दिए गए थे, लेकिन जमीन पर आज तक कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दी। इससे स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

जनसुनवाई के आवेदन बने रद्दी की टोकरी का हिस्सा...!

पीड़ित पक्ष का कहना है कि जनसुनवाई में दिए गए आवेदन अब कार्रवाई के बजाय ÷रद्दी की टोकरी÷ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी मौके पर कथित अतिक्रमण जस का तस बना हुआ है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि, अधिकारियों की लापरवाही और उदासीन रवैये के चलते अतिक्रमणकारियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर आम जनता की शिकायतों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा?

सीएम हेल्पलाइन में झूठे प्रतिवेदन लगाने के आरोप

मामले में सबसे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को लेकर सामने आ रहे हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि तहसीलदार चौहान द्वारा वास्तविक स्थिति के विपरीत प्रतिवेदन लगाकर शिकायतों को बंद करने का प्रयास किया गया।

जबकि मौके की स्थिति आज भी शिकायतकर्ताओं के आरोपों को सही साबित

कर रही है। लोगों का कहना है कि यदि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन जैसी व्यवस्था में भी गलत जानकारी देकर शिकायतें बंद की जाएंगी, तो आम जनता का भरोसा पूरी व्यवस्था से उठ जाएगा।

आखिर कार्रवाई क्यों नहीं?

अब क्षेत्र में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? क्या एसडीएम का आदेश सिर्फ दिखावा बनकर रह गया? क्या तहसील स्तर पर आदेशों की अनदेखी की जा रही है? क्या प्रभावशाली लोगों के दबाव में प्रशासन मौन बैठा है? इन सवालों ने प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर संदेह खड़े कर दिए हैं।

ग्रामीणों का आरोप है कि, अंदरखाने लेनदेन कर पूरा मामला ÷सेटल÷ कर दिया गया है।

जनता में बढ़ रहा आक्रोश

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि, यदि जल्द निष्पक्ष जांच और ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो यह मामला बड़े जनआंदोलन का रूप ले सकता है। लोगों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी सिर्फ फाइलों में कार्रवाई दिखाकर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, जबकि जमीन पर हालात पूरी तरह अलग हैं।

क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए और आवासीय भूमि से कथित अतिक्रमण हटाकर दोषियों पर कार्रवाई की जाए।

प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल

आखिर रानो गंज में ऊष्मा पेट्रोलियम के सामने स्थित आवासीय भूमि पर कथित अतिक्रमण हटाने में प्रशासन इतना लाचार क्यों दिखाई दे रहा है? क्या नियम और कानून केवल आम जनता के लिए हैं? या फिर प्रभावशाली लोगों के सामने पूरा सिस्टम घुटने टेक चुका है?

अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इस मामले में वास्तविक कार्रवाई करता है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों में दबकर रह जाएगा।

मंत्री ने छात्रावास का किया उद्घाटन

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

शहर के बोरकुणडिया में केबिनेट मंत्री नागरसिंह चौहान ने 419.33 लाख की लागत से निर्मित आदिवासी विकास विभाग छात्रावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर केबिनेट मंत्री ने कहा कि, भाजपा सरकार जो छात्रावासो की हालत खस्ता है ऐसे सभी छात्रावासों को नये भवन निर्माण कर छात्र छात्राएं अच्छे से रहकर अपनी पढ़ाई कर सके और आज बोरकुणडिया का छात्रावास इस सत्र से प्रारम्भ हो जाएगा। छात्र इसमें रहकर अच्छे से पढ़ाई अब कर सकेंगे।

माधुसिंह डावर ने कहा कि, भाजपा ने जब से सरकार बनाई तब से लेकर आज तक शिक्षा को लेकर सरकार ने काफी काम किया है। जिससे आज आदिवासी वर्ग के गरीब तबके के बच्चे छात्रावासो में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।

विशाल रावत ने कहा, कांग्रेस सरकार थी तब शिक्षा को लेकर हालात बहुत खराब थे और आज छात्रों को हर तरह से सरकार छात्रों को पढ़ाई के लिए सम्भव प्रोत्साहित कर रही है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष मकु परवाल ने भी सम्बोधित किया। बाद में भाजपा बरझर मण्डल अध्यक्ष लालसिंह चौहान के पुत्र की शादी समारोह में बोरकुणडिया निवास स्थान पहुंचे और दुल्हे राजा को आशीर्वाद दिया।

इस मौके पर मण्डल अध्यक्ष नारायण अरोड़ा, मण्डल अध्यक्ष बरझर लालसिंह चौहान, बीईओ विनोद कुमार कोरी, बीआरसी राजेन्द्र बेरागी, सरपंच विक्रम ढाक, भूपेंद्र डावर, शांतिलाल प्रजापत, चंदुलाल शाहू, मकनसिह चौहान, धन्ना लाल प्रजापत आदि मौजूद थे।

पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

पुलिस अधीक्षक आलीराजपुर रघुवंशसिंह के निर्देशन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही किये जानें के निर्देशों के पालन में थाना चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिस ने अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही करते पुलिस टीम ने ग्राम मायावाट में दबिश देकर अवैध बीयर जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। गश्त के दौरान उपनिरीक्षक भूपेंद्र सिंह को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि, ग्राम मायावाट (कनेश फलिया) निवासी कलमसिंह पिता नानसिंह कनेश ने अपने निवास स्थान पर अवैध रूप से शराब संगृहित कर रखी हुई है। मुखबीर द्वारा प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुये पुलिस टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पुलिस टीम ने बिना विलंब किए दबिश दी। दबिश के दौरान घर के अंदर एक कमरे में बडी मात्रा में शराब की 40 पेटियाँ बरामद की गईं। आजादनगर पुलिस टीम ने घटनास्?थल से अवैध शराब को विधिवत जब्त कर आरोपी कलमसिंह (45 वर्ष) को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध थाना चंद्रशेखर आजाद नगर में अपराध क्रमांक 198ध2026 के अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(1), 34(2) एवं 36 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है।

अवैध शराब के विरुद्ध इस सफल अभियान में थाना प्रभारी निरीक्षक शिवराम तरोले के नेतृत्व में सउनि भूपेंद्र नायक, सउनि तिलकराज सिंह, आरक्षक विजय लोहारे, आरक्षक भारत वास्केल एवं आरक्षक रणसिंह की विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही।

मामूली विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर हुआ हमला

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

थाना चंद्रशेखर आजाद नगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम छोटी पोल में रास्ते के मामूली विवाद को लेकर पिता-पुत्र पर फालिया और लाठियों से जानलेवा हमला किया गया। हमले गंभीर रूप से घायल बेटे की उपचार के दौरान दाहोद के अस्पताल में मौत हो गई है, जबकि उस्के वृद्ध पिता का इलाज जारी है। बेटे की मौत के बाद आक्रोशित परिजन ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में में मुख्य आरोपी सहित चार पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी माधु मावी, विक्रम, नकेश और अन्य साथियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। घटना सोमवार शाम की है।

ग्राम छोटी पोल तड़वी फलिया निवासी शैतान (32) अपनी दुकान से बड़ी पोल की तरफ जा रहा था। इसी दौरान ग्राम छोटी पोल पांगला बाबूजी की वाड़ी के सामने आम रोड मोड़ पर कट्ठीवाड़ा की तरफ से आ रही एक कार (जीजे 20 सीबी 5040) ने एक ट्रक के सामने अपनी गाड़ी अड़कर खड़ी कर दी थी। जब शैतान ने कार के ड्राइवर से गाड़ी साइड में लेकर रास्ता देने को कहा तो गाड़ी में बैठे आरोपी माधु मावी, विक्रम और नकेश उर्फ नकेसिंह तीनों नि. रठौड़ी (कट्?ठीवाड़ा) भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब शैतान ने गाली देने का विरोध किया तो माधु मावी, विक्रम और नकेश हाथ में फालिया और लकड़ी लेकर उसे मारने दौड़े। जान बचाने के लिए शैतान वहां से भागा लेकिन आरोपियों ने उसे घेर लिया।

रमेश (50) के साथ भी आरोपियों इसी बीच मौके पर पहुंचे उसके पिता ने बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी, जिससे पिता रमेश के सिर और पैर में गंभीर चोटें आई। बीच-बचाव करने पर आरोपियों ने बेटे शैतान के सिर, पीठ और पसलियों पर फालिया व लाठियों से कई घातक वार किए। वारदात के बाद आरोपी घायल पिता-पुत्र को जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर ग्राम रठौड़ी ले गए थे और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी।

जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यों का सीईओ ने किया निरीक्षण

माही की गूंज, आलीराजपुर।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती संघमित्रा गौतम ने जनपद पंचायत कट्ठीवाड़ा का भ्रमण कर विभिन्न विकास कार्यों एवं योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत अकोला में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत निर्मित अमृत सरोवर, डगवेल रिचार्ज, खेत तालाब, आंगनवाड़ी केन्द्र एवं आरोग्य सेवा केन्द्र का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। इसके पश्चात ग्राम पंचायत बड़ाखेड़ा में पंचायत भवन एवं सामुदायिक भवन तथा ग्राम पंचायत चांदपुर में डगवेल रिचार्ज कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों का जायजा लेते हुए मिशन से जुड़ी महिलाओं से चर्चा भी की गई।

भ्रमण उपरांत जनपद पंचायत कट्ठीवाड़ा के सभाकक्ष में जनपद स्तरीय अमले एवं पंचायत सचिवों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सीईओ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने पंचायत भवन, सामुदायिक भवन तथा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही अप्रारंभ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासों को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर एसीईओ वर्मा, जनपद पंचायत सीईओ प्रजापति सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

फैक्ट्री ब्लास्ट का चीन कनेक्शन...?

देवास।

टोंककला पटाखा फैक्ट्री में 14 मई को हुए भीषण विस्फोट में मृतकों का आंकड़ा बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या नौ पहुंच गई है। वहीं, मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। वहीं, इस मामले में गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष मौके पर जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने मौके पर जाकर स्थिति का मुआयना किया है।

बाहर के हैं सभी मजदूर

वहीं, मृतकों में सात मजदूर बिहार के, एक यूपी से और एक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि इंदौर में इलाज के दौरान गंभीर रूप से झुलसे राम कुमार और देवास में इलाजरत अभिषेक पासवान ने भी दम तोड़ दिया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बारूद का मिश्रण तैयार करते समय विस्फोट हुआ, हालांकि वास्तविक कारणों को लेकर पुलिस और प्रशासन एफएसएल रिपोर्ट और विशेषज्ञों की जांच का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर भी जांच जारी है।

मुख्य आरोपी है फरार

मामले में अब तक 6 आरोपियों को नामजद किया जा चुका है। इनमें से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दिल्ली निवासी कथित मास्टरमाइंड मुकेश विज अब भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इसी बीच एसआईटी ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकेश विज के भाई कपिल विज को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में कपिल विज का नाम फैक्ट्री के संयुक्त संचालक के रूप में सामने आया है। जांच एजेंसियां अब आर्थिक लेनदेन और पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं।

चीन गया हुआ है मुकेश विज

सूत्रों के मुताबिक हादसे के समय मुकेश विज पटाखा मशीन खरीदने चीन गया हुआ था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच

राज्य शासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित किया है। हाईकोर्ट के सेवा निवृत्त न्यायमूर्ति सुभाष काकड़े को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंगलवार को न्यायमूर्ति काकड़े ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ऋतुराज सिंह और एसपी पुनीत गेहलोत भी मौजूद रहे। घटनास्थल निरीक्षण के बाद न्यायमूर्ति काकड़े ग्राम कलमा स्थित जयदेव वेयरहाउस भी पहुंचे, जहां विस्फोटक सामग्री के भंडारण और सप्लाई नेटवर्क को लेकर जानकारी जुटाई गई। आयोग को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है।

एक घंटे में चार अधिकारी हुए हैं निलंबित

वहीं, हादसे के बाद शासन, प्रशासन और पुलिस स्तर पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। घोर लापरवाही और अनियमितताओं के आरोपों के बीच शनिवार को एक घंटे के भीतर चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उज्जैन संभागायुक्त ने टोंकखुर्द एसडीएम संजीव सक्सेना और टप्पा चिड़ावद के नायब तहसीलदार रवि शर्मा को निलंबित किया। वहीं, गृह विभाग ने सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे को सस्पेंड किया। इसके अलावा देवास एसपी ने टोंककला चौकी प्रभारी रमनदीप हुंडल को भी निलंबित कर दिया। लगातार हुई इन कार्रवाईयों से प्रशासनिक और पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

मजदूरों की सुरक्षा और अवैध भंडारण पर सवाल

बताया जा रहा है कि, फैक्ट्री में बिहार के 200 से अधिक मजदूर काम के लिए लाए गए थे। इनमें कुछ नाबालिग मजदूरों के भी कार्यरत होने की आशंका जताई जा रही है। आरोप हैं कि मजदूरों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।

जांच में यह भी सामने आया है कि ग्राम कलमा स्थित जिस वेयरहाउस में अनाज भंडारण होना चाहिए था, वहां भारी मात्रा में पटाखा सामग्री रखी गई थी। मजदूरों को भी उसी परिसर में ठहराया गया था।

लाइसेंस से कहीं ज्यादा विस्फोटक सामग्री मिलने के आरोप

जांच में सामने आया है कि आरोपी अनिल मालवीय के नाम जारी लाइसेंस में केवल 15-15 किलोग्राम बारूद और 600-600 किलोग्राम पटाखा सामग्री रखने की अनुमति थी, जबकि हादसे के बाद कई टन विस्फोटक सामग्री मिलने की बात सामने आई है। फैक्ट्री का लाइसेंस 31 मार्च 2026 तक वैध बताया जा रहा है, जबकि उसका नवीनीकरण 6 मई 2026 को हुआ था। ऐसे में फैक्ट्री संचालन और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

श्मोहराश् होने की चर्चा, संरक्षण के आरोप

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी तेज है कि करीब सात माह पहले तक बीपीएल कार्डधारी रहे लाइसेंसधारी आरोपी अनिल मालवीय केवल एक मोहरा था। पूरे नेटवर्क के पीछे

प्रभावशाली लोगों के संरक्षण और सहभागिता की आशंका जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में देश के चर्चित पटाखा कारोबारी मुकेश विज के कथित कनेक्शन, राजनीतिक संरक्षण और आर्थिक नेटवर्क को लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है।

पहले भी हो चुकी थीं आगजनी की घटनाएं

जानकारी के अनुसार संबंधित फैक्ट्री में पूर्व में भी आगजनी की घटनाएं सामने आ चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के आरोप लग रहे हैं। फैक्ट्री में श्एमवीश् नाम से पैकिंग वाले पटाखों का निर्माण किया जाता था। अब पूरे मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय जांच की मांग तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि यह केवल एक हादसा नहीं, बल्कि कथित लापरवाही, अवैध संरक्षण और विस्फोटक सामग्री के अवैध कारोबार का गंभीर परिणाम प्रतीत होता है।

अवैध पेट्रोल-डीजल बिक्री पर एसडीएम की कार्रवाई

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर के निर्देशन पर जिले में अवैध रूप से पेट्रोल डीजल बिक्री पर रोकथाम लगाने के उद्देश्य से सभी राजस्व अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में कट्ठीवाड़ा क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री निधि मिश्रा ने क्षेत्र का भ्रमण कर खुले में अवैध रूप से पेट्रोल एवं डीजल विक्रय कर रही दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कट्ठीवाड़ा बस स्टैंड की दो दुकानों पर अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल विक्रय करना पाया गया। एसडीएम सुश्री मिश्रा द्वारा संबंधित दुकानों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 80 लीटर पेट्रोल और 40 लीटर डीजल जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम सुश्री मिश्रा ने दुकान संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में इस प्रकार अवैध रूप से पेट्रोल-डीजल का विक्रय न करें। इस मौके पर कट्ठीवाड़ा तहसीलदार सुनील डावर, नायब तहसीलदार सुश्री सरिता बालेचा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जघन्य सनसनीखेज गंभीर प्रकरणों की समीक्षा बैठक

माही की गूंज, आलीराजपुर।

कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर की अध्यक्षता में जघन्य सनसनीखेज गंभीर प्रकरणों की समीक्षा बैठक और एनसीओआरडी समिति की बैठक कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती नीतू माथुर द्वारा जघन्य सनसनीखेज गंभीर प्रकरणों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा जिले में दर्ज जघन्य गंभीर प्रकरणों के बारे में बताया गया। कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि कोई भी प्रकरण साक्ष्य के अभाव में लंबित न रहे साथ ही जो संवेदनशील प्रकरण दर्ज है उन्हें गंभीरता से लेते हुए उनकी सुनवाई कर जल्द से जल्द निराकरण करे।

कलेक्टर द्वारा नारकोटिक्स एवं नशीली दवाओं की रोकथाम को लेकर एनसीओआरडी समिति से इस विषय पर चर्चा कर पिछले एक माह में नशीले पदार्थों की रोकथाम हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और अवैध खरीदी-बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों एवं फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

बैठक में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा बताया गया कि उन्होंने नशा मुक्ति अभियान के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में उपस्थित जनों को नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाई गई थी। वहीं कलेक्टर श्रीमती माथुर ने औषधि निरीक्षक को मेडिकल स्टोर्स की नियमित जांच एवं बिना चिकित्सकीय पर्चे के प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर कठोर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।

कलेक्टर श्रीमती माथुर ने यह भी कहा कि की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से कलेक्टर कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही नागरिकों को नारकोटिक्स से जुड़े कानूनों और उल्लंघन पर होने वाली कानूनी कार्रवाई की जानकारी देकर जागरूक किया जाए, ताकि वे इन कार्यों में संलग्न ना हो। उन्होंने सभी विभागों को इस दिशा में गंभीरता से कार्य करने और समन्वय बनाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती संघमित्रा गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल सहित शिक्षा, कृषि और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

जिले के हर कस्बे में चल रहे फर्जी आरओ वॉटर प्लांट या फिर वॉटर चिलर...? पेयजल गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं

जिला प्रशासन का कोई ध्यान नहीं, मगर जिले के ग्रामीण नालों और पोखरों में झीरी खोद कर पानी पीने को मजबूर

माही की गूंज, झाबुआ। मुजम्मिल मंसुरी

वैसे तो झाबुआ जिला पहले ही पेयजल अभाव ग्रस्त घोषित हो चुका है। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण वर्तमान में नालों और पोखरों में झीरी खोदकर पानी पीने को मजबूर है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। या फिर यह कहना भी गलत नहीं होगा कि, प्रशासन के कागजी घोड़े इतनी रफ्तार से दौड़ रहे है कि, वह जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में पेयजल उपलब्ध करा चुके है। गांव-गांव में बड़ी-बड़ी पेयजल की टंकियां खड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल वैसी है जैसे कि 'हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर'। हकीकत में जिन गांवों में नल-जल योजना या जल जीवन मीशन के तहत टंकियां और पेयजल पाइन लाईन बिछाई गई है और घर-घर नल से जल पहुंचाने के दावे किए जा रहे वह महज शो पीस साबित हो रहे है। कई गांवों में इन योजनाओं के तहत हितग्राहियों के घर तक नल तो पहुंच गए लेकिन उनमें पानी अब तक नहीं पहुंच पाया है। जमीनी हकीकत पर अगर नजर डाले तो वर्तमान समय में जिले के कई गांव और फलिये ऐसे है जहां ग्रामीण लोगों को पेयजल के लिए जद्दो जहद करते देखा जा रहा है। कई जगह लोग नालों और पोखरों में पेयजल के लिए झीरी खोद कर पानी निकाल रहे है तो कई ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के लिए कई किलो मीटर का सफर कर रहे है। लेकिन प्रशासन है कि अपने कागजी घोड़े दौड़ाने में व्यस्त है।

एक तरफ तो जिले में जल संकट से जूझते ग्रामीणों की खबरें समाचार-पत्रों में जगह बना रही है। तो वहीं जिले के लगभग हर कस्बे में पेयजल का खुला व्यापार धड़ल्ले से जारी है। आरओ पेयजल के नाम पर हर कस्बे व ग्राम में कम से कम एक आरओ वाटर प्लांट या वाटर चिलर प्लांट जरूर मिल जाएगा। बकायदा इन प्लांटों से पेयजल बेचा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा जिला पेयजल अभाव ग्रस्त घोषित किया जा चुका है। अभी मानसून में भी देरी है और जिले में पेयजल संकट को लेकर जो स्थिति है वह चिंतनीय है। पेयजल आपुर्ति के लिए प्रशासन एक तरफ तो निजी बोरवेल, नलकूप, कुंए अधिगृहित करता है। लेकिन जिले में चलने वाले सैकड़ों आरओ फिल्टर वाटर प्लांट या वाटर चिलर प्लांट पर अब तक जिला प्रशासन की नजर नहीं पहुंची है या फिर जिला प्रशासन जानबूझ कर इसे अनदेखा कर रहा है। स्थिति का जब जायजा लिया गया तो पता चला कि, जिले के हर छोटे से छोटे कस्बे में कम से कम एक प्लांट हे ही ओर वो ऐसा है जो आरओ वाटर के नाम पर पानी को ठंडा कर बैच रहा है। इस तरह के वाटर प्लांटों पर प्रशासन की कोई सख्ती अब तक दिखाई नहीं दी है। रही बात इन वाटर प्लांटों से सप्लाय होने वाले पेयजल की गुणवत्ता की तो यहां भी प्रशासन की रूची जीरो बटे सन्नाटा ही दिखाई दे रही है। क्योंकि प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार ने आज तक यह जानने की कोशिश नहीं की कि, इन वाटर प्लांटों से क्या सही में आरओ का पानी सप्लाय किया जा रहा है...? जबकि इन प्लांटों से सप्लाय होने वाले पानी की कीमत आरओ का पानी बता कर वसूली जा रही है...? देखा जाए तो यह खुले रूप से जिले में पेयजल की माफियागिरी ही कही जा सकती है। जबकि जिला पेयजल अभावग्रस्त प्रशासनिक तौर पर किया जा चुका है। तो फिर इस तरह के वाटर प्लांटों से पानी को क्या लायसेंस लेकर बैचा जा रहा है...? अगर ऐसा नहीं है तो फिर प्रशासन और उसमें बैठे जिम्मेदार कहां है...?

फाईल फोटो

जिले में पेयजल समस्या के चलते इन दिनों इन पेयजल माफियाओं की खूब चांदी हो रही है। जिला आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और वर्तमान में आदिवासी समाज में भी शादी ब्याह का सीजन चल रहा है। ग्रामीण अंचलों में जहां भी शादी ब्याह के आयोजन हो रहे है वहां इन फर्जी आरओ वाटर प्लांटों के डब्बे आसानी से देखे जा रहे है। जो सभी समाजवर्गों को आरओ का फिल्टर पानी बताकर सिर्फ डब्बों में ठंडा पानी सप्लाय कर रहे है। मगर आवाज उठाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि प्रशासन भी इस तरह के गंभीर मुद्दे पर अपनी तरफ से किसी तरह की जांच पड़ताल करता अब तक दिखाई नहीं दिया है। अवैध वाटर प्लांटों से डब्बों में सप्लाय होता यह पानी पीने योग्य भी है या नहीं कोई नहीं जानता...?

बात सिर्फ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों या कस्बों में चलने वाले इस तरह के फर्जी आरओ वॉटर प्लांट की नही है। जिला मुख्यालय पर भी इस तरह के दर्जनों आरओ वॉटर प्लांट संचालित हो रहे है। जिन की जांच करने की जहमत आज तक तंत्र में बैठे किसी जिम्मेदार ने नहीं उठाई है। उस पर सितम यह है कि, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में कोई 30 में आरओ वाटर का डब्बा सप्लाय कर रहा है तो कोई नेहले पर देहला देते हुए 20 रुपए प्रति डब्बा में ही पानी की सप्लाय कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर आप मासिक बंदी इन पानी के डब्बों की लगाते है तो यह आपको बहुत ही कम कीमत में 400 या 500 रुपए मासिक में ही दुकानो व घरो में उपलब्ध हो जाएगा। जिला मुख्यालय पर लगे इस तरह के वॉटर प्लांटों से सप्लाय की बात अगर की जाए तो हर एक प्लांट से लगभग 500 से 700 डब्बे पानी रोज मुल्य लेकर खपाया जा रहा है। इस अनुमान के अनुसार अगर गणना की जाए तो लगभग जिला मुख्यालय पर ही इन फर्जी वॉटर प्लांटों से लगभग 9 से 10 हजार डब्बे पानी के सप्लाय हो रहे है। बावजूद इसके इस तरह के वाटर प्लांटों से निकलने वाले पानी की गुणवत्ता की कोई गारंटी नही है।

ईश्वर न करे कि अगर जिले में किसी एक भी फर्जी वाटर प्लांट से इंदौर के भागीरथपुरा में हुई घटना जैसी घटना घटित होती है तो फिर क्या होगा समझा जा सकता है। इस स्थिति में इन फर्जी वॉटर प्लांटों की जिम्मेदारी और होने वाली बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी क्या प्रशासन उठा पाएगा...? क्योंकि यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि, इस तरह के एक फर्जी आरओर वाटर प्लांट से जब 500 से 700 डब्बे पानी रोज सप्लाय होता है तो वह कितने लोगों तक पहुंचता होगा या कितने परिवारों तक पहुंचता होगा...? अगर कहीं कुछ अनहोनी हुई तो यह अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितने लोग इसकी चपैट में आएंगे। क्योंकि इस तरह के फर्जी आरओ वॉटर प्लांटों से अक्सर ऐसे पानी के डब्बे लोगों तक पहुंचते रहते है जिनमें या तो गंदगी पाई जाती है या फिर कोई किड़ा पानी के अंदर पाया जाता है या फिर पानी के साथ डब्बे में मिट्टी निकलती है। जिन डब्बों में पानी सप्लाय होता है उनकी सफाई पर भी कई सारे सवाल है। यह कोई नहीं जानता कि पेयजल सप्लाय करने वाले डब्बे कितने दिनों में साफ होते है या धुलते है...?

इसलिए जिला प्रशासन को चाहिए कि वह जिले में चलने वाले सभी आरओ वाटर सप्लायरों की जांच करे। उनके लायसेंस चैक करें, पेयजल की गुणवत्ता भी चेक करे। साफ-सफाई का भी अवलोकन करे। अनियमितता होने पर कठोर कार्रवाई करे। ताकि जिले में इस डब्बा बंद पेयजल से होने वाली किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

सप्ताह में दो दिन मुख्यालय पर तो एक दिन रात्रि विश्राम के कलेक्टर के आदेश पर पटवारियों में हलचल...?

नियम तो यह कि हर कर्मचारी को अपने पदस्थापना मुख्यालय पर रहना है, लेकिन हकीकत में स्थिति ढाक के तीन पात

माही की गूंज, झाबुआ।

इन दिनों कलेक्टर के एक आदेश ने जिले के पटवारियों में हलचल मचा कर रख दी है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अब पटवारियों को हर सप्ताह दो दिन सोमवार और गुरूवार को अपनी संबंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। आदेश में विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि, प्रत्येक पटवारी जनसुनवाई के दिन और सप्ताह में एक दिन गुरूवार को अनिवार्य रूप् से ग्रामीण क्षेत्र में ही रात्रि विश्राम करेगा। इस दौरान पटवारियों को उनके द्वारा किए गए कार्यों का पूरा विवरण एक रजिस्टर में संधारित करना होगा। जिसका निरीक्षण और प्रमाणीकरण संबंधित एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार करेंगे। कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया है कि, वे पटवारियों की उपस्थिति और कार्यों की नियमित रूप से समीक्षा करें।

कलेक्टर कार्यालय से जारी उक्त आदेश से जिले के 315 पटवारियों में हलचल सी मच गई है। वैसे तो यह आदेश किसी भी पटवारी को हजम नहीं हो रहा है। लेकिन दबी जुबान से सभी पटवारी महिला पटवारियों के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे है। क्योंकि जिले में 315 में से लगभग 78 महिला पटवारी कार्यरत है। पटवारी संघ की ओर से जारी वक्तव्यों के अनुसार प्रशासन को जिले की व्यावहारिक और भौगोलिक स्थिति को भी समझना होगा। हमारी मांग है कि, प्रशासन इस व्यावहारिक संकट को समझे और इस आदेश में संशोधन करते हुए महिला पटवारियों को रात्रि विश्राम की अनिवार्यता में छूट प्रदान करे।

इस आदेश के बाद पटवारियों ने महिला पटवारियों का पक्ष लेते हुए कई सारी समस्याओं का बखान किया है। जैसे अकेली महीला पटवारी किस तरह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रात्री में विश्राम कर सकती है। जबकि ग्रामीण अंचल में बिजली को लेकर काफी समस्या बनी रहती है। कई पंचायत भवनों में शौचालय का भी अभाव है तो भौगोलिक स्तर पर कई तरह की समस्याएं महिला पटवारियों को हो सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में सुरक्षा के इंतेजाम भी न के बराबर होते है। ऐसी स्थिति में महिला पटवारियों का ग्राम पंचायतों में रात्रि विश्राम कई चुनौतियां खड़ी कर सकता है। खैर कलेक्ट्रोरेट से यह आदेश जारी तो हो गया है लेकिन अब देखना यह है कि, क्या महिला पटवारियों के पक्ष में इसमें कुछ संशोधन हो पाएगा।

हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जबकि किसी कलेक्टर ने इस तरह के आदेश जारी किए हो। नियम के अनुसार मध्यप्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने पदस्थापना के मुख्यालय पर ही रहना होता है। हालांकि इसके परिपालन की स्थिति जिले में बड़ी ही गंभीर है। क्योंकि जिले में 90 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी ऐसे है जो अपनी पदस्थापना मुख्यालय पर नहीं रहते है। इनमें सबसे बड़ी संख्या शायद शिक्षकों की है। वैसे तो ग्रामीण क्षेत्र में तैनात हर कर्मचारी करीबी किसी बड़े कस्बे या शहर में ही निवास करते है। तो कुछ कर्मचारी ऐसे भी है जो जिले में नहीं रहते बल्कि करीबी जिलों से डेली अप-डाउन करते हैं। इस स्थिति को प्रमाणित करने की भी आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि जिले से होकर चलने वाली सवारी बसों और ट्रेनों में ऐसे कर्मचारियों की भीड़ रोज ही सफर करती है।

इससे पहले भी कई कलेक्टरों ने इस तरह के आदेश सख्ती से जारी किए है कि, कर्मचारियों को अपनी पदस्थाना मुख्यालय पर ही रहना है। लेकिन अधिकारियों के तबादले के बाद स्थिति ढाक के तीन पात हो जाती है। पटवारियों पर जारी किया गया कलेक्टर का यह निर्देश सही है पर कितने दिन और कैसा काम करता है यह तो समय के गर्भ में है। लेकिन जिले का इतिहास यह भी बताता है कि, ऐसे आदेशों -निर्देशों की स्थिति जल्द ही ढाक के तीन पात हो जाती है।

जिले का इतिहास उठाकर अगर देखें तो यहां यूं तो कई कलेक्टरों ने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रात्रि विश्राम किया है। कई मंत्री भी जिले के ग्रामीण अंचलों में रात्रि विश्राम कर चुके है। हालांकि इस तरह के घटनाक्रम को घटे जिले में शायद दशक भर से ज्यादा हो गया। तो क्या अब कलेक्टर फिर से इस राह पर चलकर खुद भी ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम करेंगे...?

रही बात नियम की तो नियम कहते है कि मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने पदस्थापना के मुख्यालय पर ही रहना होता है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के तहत विभागीय कार्रवाई और निलंबन तक हो सकता है। सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासकीय कार्यों के प्रति तत्परता और आपातकालीन स्थितियों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यक्षेत्र के मुख्यालय में ही रात्रि निवास करना अनिवार्य है। यदि मुख्यालय पर आवास की समस्या हो, तो वरिष्ठ अधिकारियों (कलेक्टर, विभागाध्यक्ष) की विशेष अनुमति से कर्मचारी अपने मुख्यालय के 8 किलोमीटर के दायरे में निवास कर सकते है।

मुख्यालय में न रहने पर 'गृह भाड़ा भत्ता' की पात्रता प्रभावित होती है और यदि कर्मचारी मुख्यालय में रहने का फर्जी पता देकर भत्ते का लाभ लेते हैं, तो यह धोखाधड़ी मानी जाती है। बिना लिखित अनुमति के मुख्यालय छोड़ने या मुख्यालय पर अनुपस्थित पाए जाने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आचार संहिता या आपातकालीन परिस्थितियों में जिला प्रशासन द्वारा सभी कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। यदि किसी कर्मचारी को अपरिहार्य कारणों से मुख्यालय से बाहर जाना हो, तो उन्हें अपने उच्च अधिकारी से पूर्व स्वीकृति (लिखित अवकाश या अनुमति) प्राप्त करना अनिवार्य है। सामान्य प्रशासन विभाग या संबंधित विभाग के स्थापना शाखा के दिशा-निर्देशों में इसका स्पष्ट उल्लेख होता है।

इस तरह के नियम निर्देशों के पालन करवाने की जिले में अति आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। तो पटवारियों के साथ-साथ कलेक्टर को चाहिए कि वे तमाम शासकीय कर्मचारियों को नियम अनुसार चलने पर बाध्य करें। ताकि जिस तरह पटवारियों के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रूकने से ग्रामीणों व आम जनता का भला व काम हो सकेंगे, उसी तरह सभी शासकीय कर्मचारियों के पदस्थापना मुख्यालय पर रहने से कई तरह के फायदे जिले की आमजनता को होंगे।

माही की गूंज : खबर का असर

शासन तत्काल स्वीकृति दे...

माही की गूंज, खवासा।

जिले के वरिष्ठ आदिवासी नेता स्व. दिलीप सिंह जी भूरिया अपने भाषणों में अक्सर मुहावरे का प्रयोग करते थे कि, ''नाचे कूदे वान्दरी और खीर खाए फकीर'' भावार्थ यह था कि काम कौन करें और श्रेय और फायदा और कोई ले। ठीक उसी तर्ज पर झाबुआ जिले के अंतिम छोर पर खवासा क्षेत्र के कुकड़ीपाड़ा के माही तट पर बन रहे तलावड़ा बैराज की स्थिति थी। यानी यह बन तो रहा है झाबुआ जिले की सीमा में लेकिन इसका लाभ रतलाम और धार जिले के 808 गांव में मिलना था। झाबुआ जिले के सैकड़ो गांव जल संकट से झुझ रहे हैं उनके लिए इस योजना में कोई प्रावधान नहीं था यानी दिया तले अंधेरा। रतलाम और धार जिले के 808 गांवो को पेयजल देने वाला झाबुआ जिला खुद प्यासा ही इस योजना में रह रहा है। जिसको लेकर जिले के प्रमुख समाचार-पत्र माही की गूंज ने लगातार समाचार प्रकाशित किए। जिसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग के अधिकारियों की नींद खुली और इस योजना को झाबुआ जिले के 90 गांवो के लिए भी पेयजल आपूर्ति का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा है। अब गेंद शासन के पाले में है ऐसे में शासन द्वारा स्वीकृति मिलने के पश्चात झाबुआ जिले के 90 गांव को भी पेयजल उपलब्ध हो सकता है। ऐसे में थांदला विधानसभा के खवासा व क्षेत्र को भी पानी मिल सकता है। जहां अमूमन बारहमासी जल संकट रहता है और जल संकट को लेकर नागरिकों ने दलगत राजनीतिक से ऊपर उठकर एक बड़ा आंदोलन भी किया था। जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं खाली बर्तन लेकर सड़कों पर उतरी थी और धरना प्रदर्शन किया था जो कि मात्र आश्वासन पर ही खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी समस्या जस की तस बनी हुई है इस योजना के विस्तार की खबर के बाद खवासावासियों के साथ खवासा व बामनिया क्षेत्र को भी उम्मीद की किरण दिखाई देने लगी है।

विडंबना: झाबुआ जिले की भूमि पर बन रहा डेम, जिले की भूमि से ही काली मिट्टी ले जाकर किया जा रहा कार्य

झाबुआ जिला व क्षेत्र में भी उक्त बांध से पानी मिले जिसकी कार्य योजना प्रशासन व सरकार को बनाने हेतु माही की गूंज ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा।

दिया तले अंधेरा... कुम्हार के लिए फूटी हांडी भी नहीं...

क्या है तलावड़ा बैराज

264 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे तलावड़ा बैराज करीब 600 मीटर लंबा और 32 मीटर ऊंचा रहेगा। इसकी कुल भराव क्षमता 67.02 एमसीएम (लगभग 67 अरब लीटर) होगी।

मौजूदा कार्य योजना के तहत इस पानी से रतलाम और धार जिले के 808 गांवो को पेयजल सप्लाई किया जाना है। इन गांव में पर्याप्त पेय जल सप्लाई के बाद भी बैराज में बहुत अधिक पानी शेष बचेगा जिसको लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने झाबुआ जिले के 90 गांवो के लिए बैराज से लगभग 12 एससीएम (12 अरब लीटर) पानी रिजर्व रखने की मांग की है। और शासन स्तर से मंजुरी मिलने के बाद यह पानी जल निगम को सौंप दिया जाएगा। और अगर मंजूरी मिलती है तो जिले के 90 गांवो को भी इस योजना का लाभ मिलने लगेगा और खवासा जैसे गांवो की वर्षो पुरानी समस्या भी हल हो सकती है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422